Page-01_Layout 1 3/4/2025 12:46 AM Page 1

■ वर्ष-17 ■ अंक-44 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य : 1 रुपए

नई दिल्ली, मंगलवार, 4 मार्च, 2025

newdibyabharat@gmail.com

विधानसभा की गरिमा और अनुशासन सर्वोपरि : विजेंद्र गुप्ता पृष्ठ-2

दिव्य भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

साल 2014 के बाद रेलवे में सूचीबद्ध सभी सातों सार्वजनिक पृष्ठ-3

भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में आपकी निर्णायक भूमिका : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों से कहा है कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी निर्णायक भूमिका है। उन्होंने शिक्षण के साथ-साथ शोधकार्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रपति मुर्मु सोमवार को राष्ट्रपति भवन में दो दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति 184 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की विजिटर हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 8वें विजिटर अवार्ड-2023 के पांच विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण में कहा कि किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में साफ झलकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों से कहा कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ शोध पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत सरकार ने बहुत अच्छे उद्देश्य से राष्ट्रीय

अनुसंधान कोष की स्थापना की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च शिक्षा संस्थान इस महत्वपूर्ण पहल का अच्छा उपयोग करेंगे और शोध को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के उच्च शिक्षण समुदाय की महत्वाकांक्षा यह होनी चाहिए कि हमारे संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं को विश्वस्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए। हमारे संस्थानों के पेटेंट विश्व में बदलाव ला सकें और विकसित देशों के विद्यार्थी भारत को उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में चुनें।

त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है तीन नए आपराधिक कानूनों की प्राथमिकता : शाह

रमाकान्त पाण्डेय

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, गोवा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएडंडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और गोवा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की प्राथमिकता त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के अमल के मामले में गोवा

देश में आदर्श राज्य बने। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए जांच और अभियोजन में समययसीमा का सख्ती से पालन होना चाहिए। सात वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषसिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने ई-साक्ष्य पर सभी जांच अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने गोवा में ई-समन को 31 मार्च तक पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया।

गृहमंत्री ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग के मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन अपराधों से जुड़ी धाराओं का दुरुपयोग न हो। इन मामलों से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज करने से पहले पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से अनुमति ली जानी चाहिए। पुलिस को अपराधियों के पास से बरामद की गई संपत्ति को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उसके असली हकदार को लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। फॉरेन्सिक नमूनों की जांच को शत-प्रतिशत तक लाने के लिए सख्ती से काम करें। गोवा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें।

भारत 2027 तक दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना लेगा : राजनाथ

आलोक पाण्डेय

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण में पूरे दिल से योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। भारत के सैनिक हमेशा कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं पर दृढ़, सतर्क और तैयार रहते हैं तथा साहस और तत्परता के साथ देश को सभी प्रकार के खतरों से बचाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे बढ़कर हर संभव तरीके से उनका समर्थन करना राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है।

नई दिल्ली में सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एएफएफडी सीएसआर) सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने तथा अपने सैनिकों के साथ ही उनके परिजनों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएसआर का मतलब सिर्फ 2 प्रतिशत योगदान नहीं है, बल्कि यह वीर सैनिकों और उनके आश्रितों से दिल से दिल का जुड़ाव है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित शीर्ष कॉर्पोरेट प्रमुखों से कहा कि आप जो भी योगदान देंगे, वह साधारण नहीं होगा। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कल जब आपकी वास्तविक बैलेंस शीट तैयार होगी, तो उसमें देनदारियों से ज्यादा संतुष्टि और खुशी की संपत्तियां होंगी।

सीएसआर कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार की निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयासों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ भारत 2027 तक दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लेगा। उन्होंने एएफएफडी फंड में उदारतापूर्वक योगदान के लिए कॉरपोरेट घरानों की सराहना की और इस अवसर पर शीर्ष सीएसआर दानदाताओं को सम्मानित किया।

रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग युद्ध विधवाओं, शहीद सैनिकों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्य कर रहा है, जिनमें दिव्यांग भी शामिल हैं। इसके लिए उन्हें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे निर्धनता अनुदान, बच्चों की शिक्षा का अनुदान, अंत्येष्टि अनुदान, चिकित्सा अनुदान और अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आईआरसीटीसी, आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सीपीएसई में 25वां नवरत्न बन जाएगा। आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार 4,270.18 करोड़ रुपये, पीएटी 1,111.26 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नेटवर्थ 3,229.97 करोड़ रुपये है। डीपीई ने एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सीपीएसई के बीच 26वां नवरत्न बन जाएगा। आईआरएफसी रेल मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार 26,644 करोड़ रुपये, पीएटी 6,412 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 49,178 करोड़ रुपये का नेटवर्थ है।

रेलवे कर्मचारी कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी

जयपुर, (हि.स.)। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। राज्य विशेष शाखा जयपुर ने पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के दौरान इस कॉल को ट्रेस किया था, जिसके बाद कॉल पर काम करने के दौरान इंटेलिजेंस की टीम आरोपित तक पहुंच सकी। गिरफ्तार रेलवे कर्मचारी कई माह से निमी नाम की महिला के सम्पर्क में था और कई जानकारी साझा कर चुका था। जांच के दौरान इंटेलिजेंस की टीम को कई साक्ष्य आरोपित भवानी सिंह के खिलाफ मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया।

इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने बताया कि बीकानेर जिले के सामरिक महत्व से अति संवेदनशील महाजन रेलवे स्टेशन क्षेत्र की निगरानी के दौरान टीम ने यहां पदस्थापित पॉइंटमैन भवानी सिंह को गिरफ्तार किया। भवानी सिंह की गतिविधियां संदिग्ध होने पर उस पर टीम ने निगरानी रखना शुरू किया, पुष्टि होने पर दो दिन पहले भवानी को डिटेन कर जयपुर लाया गया जहां पर पूछताछ में कई जानकारी सामने आई। पूछताछ के बाद सोमवार को उसे गिरफ्तार किया गया।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना का अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सैन्यकर्मियों एवं सेना के सभी प्रकार के सामान का आवागमन महाजन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होता है। भवानी सिंह ने युवती के फेर में फंस कर हनीट्रैप का शिकार हुआ साथ ही उस ने धन के लोभ में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में रह कर महाजन रेलवे स्टेशन पर सेना की होने वाली सभी गतिविधियों की संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना निरंतर देता रहा। इन सभी प्रकार की जानकारी देने की एवज में भवानी सिंह ने आईएसआई से पैसा ले रहा था।

भारत और नेपाल के बीच जल व स्वच्छता सहयोग को मजबूत करने को लेकर हुआ करार

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारत और नेपाल ने आज अपशिष्ट प्रबंधन सहित जल, स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता यहां सुषमा स्वराज भवन में भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और नेपाल सरकार के जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव की उपस्थिति में हुआ।

समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और आरोग्य क्षेत्र में अंतर-सरकारी सहयोग को मजबूत करना है, जिससे उनकी आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। व्यापक समझौता ज्ञापन

में कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक रूपरेखा तय की गई है। इसमें क्षमता निर्माण के तहत जल संसाधन प्रबंधन और संबंधित क्षेत्रों में नेपाली कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण के तहत भारत और नेपाल के बीच आरोग्य क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसके अलावा भूजल प्रबंधन के तहत गुणवत्ता सुधार, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन सहित भूजल संसाधनों की निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन में संयुक्त प्रयास साझा करना है।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पाटिल ने जोर देकर कहा कि यह समझौता ज्ञापन सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत और नेपाल की साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने बड़े पैमाने पर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पहलों को लागू करने में भारत की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नेपाल इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव से सीखने के लिए उत्सुक है और नेपाली अधिकारी अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगे। उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि स्थिर प्रगति और ज्ञान के पारस्परिक आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

इस साल मई में कराई जाएगी भारत के एशियाई शेरों की गणना : प्रधानमंत्री

जूनागढ़, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चीता सरंक्षण योजना को मध्य प्रदेश में गांधीसागर अभयारण्य और गुजरात में बन्नी घास के मैदानों सहित अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने, डॉलफि न और एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयास तेज करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने एशियाई शेरों की गणना इस वर्ष कराने की घोषणा की। मोदी ने जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को गुजरात के सासण गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने के बाद यहां नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीएफडब्ल्यूबी) की सातवीं बैठक में शामिल हुए। एनबीएफडब्ल्यूबी की इस बैठक में वन्यजीव संरक्षण में सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा की। बैठक में नए संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण

और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जैसे प्रजाति-विशिष्ट प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

बोर्ड बैठक में डॉलफि न और एशियाई शेरों के संरक्षण प्रयासों और इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस की स्थापना पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पहली बार आयोजित रिवरिन डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि कुल 6,327 डॉलफि न हैं। इस प्रयास में आठ राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण शामिल किया गया है। इसकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है।घड़ियाल की घट रही आबादी को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताते हुए सरंक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गिर के सिंह और चीता के सरंक्षण की सफलता की कहानी को बताया। उन्होंने कहा कि परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के उपयोग के लिए एआई की सहायता से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने वन्य औषधियों के शोध और दस्तावेजीकरण की भी सलाह दी।

बैठक में प्रधानमंत्री ने मई 2025 में एशियाई शेरों की गणना कराने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने जंगलों में लगने वाली आग, मानव-पशु संघर्ष जैसे मुद्दों के समाधान पर चर्चा की। उन्होंने अभ्यारण्य के बाहर बाध संरक्षण पर केंद्रित एक योजना शुरू करने की घोषणा की।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी। यह केन्द्र वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समन्वय और प्रशासन के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। एशियाई शेरों की आबादी का अनुमान हर पांच साल में एक बार लगाया जाता है।

Page-02_Layout 1 3/3/2025 10:43 PM Page 1

नई दिल्ली में सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और उनके समकक्ष थियो फ्रेंकेन ने मुलाकात की।

भाजपा ने कैग रिपोर्ट को लेकर आप पर निशाना साधा

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के बजट सत्र की घोषणा पर कैग की रिपोर्ट को लेकर आआपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कैग की रिपोर्ट पर बात करे, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। वीरेंद्र सचदेवा ने यहां एक बयान में कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से शुरू होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। भाजपा की सरकार दिल्ली के विकास के लिए कार्य करेगी। सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में दिल्ली का विकास रुका हुआ है, उसके लिए भाजपा की सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचा है। पिछले सात-आठ दिनों में ही योजना बनाकर और मीटिंग करके अपना काम शुरू कर दिया है। यह बजट दिल्ली के लोगों के लिए होगा।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यह बजट दिल्लीवासियों के सुझावों के अनुसार तैयार किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने इस पर कई बैठकें की हैं।

विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से मिलकर विधानसभा अभिभाषण के लिए आभार जताया

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भेंट की। मुलाकात के दौरान गुप्ता ने 25 फरवरी को विधानसभा में दिए गए उपराज्यपाल के अभिभाषण के लिए सदन की ओर से औपचारिक रूप से उनका आभार व्यक्त किया।

विधानसभा में पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर उपराज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की गई थी। नियम 19(7) के तहत विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज व्यक्तिगत रूप से एक औपचारिक पत्र सौंपा और सदन की ओर से उपराज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सम्मान प्रकट किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल का अभिभाषण दिल्ली के विकास और सुशासन के रोडमैप को लेकर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छे माहौल में हुई।

दरअसल, हर साल दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरूआत में उपराज्यपाल का अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार की नीतियों, विकास योजनाओं और आने वाले साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया जाता है। इस बार 25 फरवरी को उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी अहम योजनाओं पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। उपराज्यपाल ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि सुशासन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनका मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर जनता के हित में काम करना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से, मुख्यमंत्री ने व्हाटसएप और ई-मेल पर मांगी जनता से राय

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक होगा। विकसित दिल्ली के इस बजट के लिए सरकार राजधानी के विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने का प्रयास करेगी ताकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बजट बनाया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ यहां आहूत एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 24 से 26 मार्च के बीच पेश किया जाएगा। इसमें दिल्ली के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने का पुरजोर प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना, यमुना की सफाई, रोजगार, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रमुखता से जिक्र किया गया था। अब हमारा उद्देश्य दिल्ली के लोगों की इन तमाम प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना और उसके अनुसार बजट की रूपरेखा तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझावों को लें और उन्हें बजट में शामिल करें। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर (999962025) शुरू किया गया है, जिससे दिल्ली का कोई भी नागरिक अपने सुझाव दे सकता है। सरकार ने 5 मार्च को महिला संगठनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। छह मार्च को व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह आम आदमी का बजट हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी मंत्री और विधायक बजट पर जनता की अपेक्षाओं को जानने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। हमारी सरकार दिल्ली के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही है, इसलिए अबकी बार बजट भी वही पेश करेंगी।

लूटपाट के मामले में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तर पश्चिमी जिले के केशवपुरम थाना पुलिस ने लूटपाट के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मेरठ निवासी मोहित कुमार (27) और लोनी गाजियाबाद निवासी आबिद (29) के रूप में हुई है।

उत्तर पश्चिमी जिले के डीसीपी भीष्म सिंह ने सोमवार को बताया कि 26 फरवरी को केशवपुरम थाना पुलिस को पेंटामेड अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को किसी ने गोली मारी है और घायल युवक उनके अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। जांच में घायल युवक की पहचान केशव पुरम निवासी नितिन (37) के रूप में हुई। घायल बयान देने की हालत में नहीं था। घायल को अस्पताल में भर्ती कराने वाले रिश्तेदार पुनीत, राहुल और सचिन ने पुलिस को बताया कि नितिन ने उन्हें फोन करके बताया था कि उसे बी-4 के पास गोली मारी है, मदद कर दो।

डीसीपी के अनुसार पुलिस की एक टीम को घटनास्थल के पास भेजा गया। घटनास्थल पर पूछताछ करने पर पता चला कि घटना के वक्त नितिन कार में बैठे थे। उसी दौरान दो हमलावर आए और पहले कार की खिड़की पर ईंट मारी उसके बाद खिड़की के शीशे पर गोली चला दी। नितिन को गोली मारने के बाद हमलावर उसका बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लूटपाट व हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहित को दिल्ली हरिद्वार हाइवे के पास से दबोचा। पूछताछ में मोहित ने खुलासा किया कि उसके दोस्त कादिर ने उसे आबिद उर्फराज से मिलने के लिए कहा था, जो नितिन को लूटने की साजिश रच रहा था। आबिद को नितिन को नकदी के बदले कुछ सामान देना था। मोहित की मुलाकात लोनी में आबिद से हुई, जिसने उसे फोन पर हैदर अली नाम के एक व्यक्ति से मिलाया, जिसने बताया कि उन्हें केशव पुरम में नितिन उर्फ अभिषेक से मिलना है।

आरोपितों ने नितिन से संपर्क किया और उन्होंने 26 फरवरी को बी-4, केशव पुरम में मिलने के लिए बुलाया। इधर आरोपित एक अन्य सहयोगी रवि के साथ स्विफ्ट डिजायर टैक्सी से केशव पुरम पहुंचे जबकि कादिर और आबिद मोटरसाइकिल से केशव पुरम पहुंचे। वह नितिन से मिला और नितिन के साथ कार में बैठते हुए उसने अपने अन्य सहयोगियों को इस बात की पुष्टि की कि नितिन नकदी लेकर आया है। उसके बाद आबिद ने कार की खिड़की तोड़ने के लिए उस पर गोली चलाई। आरोपित के अनुसार नकदी देने से मना करने पर उसके साथियों ने नितिन को गोली मार दी। उसके बाद उनके साथी पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर इसके साथी कादिर को दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

आज का राशिफल

मेष राशि–प्रत्येक कार्य में बाधा, विलम्ब कष्टप्रद होगा, थकावट व बेचैनी बनेगी।

वृष राशि–कुटुम्ब की समस्याओं में समय बीतेगा, धन का व्यय, चिन्ता बढ़ जायेगी।

मिथुन राशि–स्त्री वर्ग से हर्ष-उल्लास, प्रेम-प्रसंग सफलता से कार्य अनुकूल अवश्य होंगे।

कर्क राशि–आर्थिक योजना पूर्ण होगी, भाग्य का सितारा प्रबल होगा, रुके कार्य बनेंगे।

सिंह राशि–भाग्य की प्रबलता का लाभ लें, रुके कार्य समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें।

कन्या राशि–मान-प्रतिष्ठा, प्रभुत्व वृद्धि, नवीन योजना फलप्रद होगी, कार्य पर ध्यान दें।

तुला राशि–मनोबल उत्साहवर्धक होगा, कार्यगति में सुधार होगा, विरोधी पराजित होंगे।

वृश्चिक राशि–लेन-देन के कार्य में हानि होगी, विरोधी तत्वों से परेशानी अवश्य बनेगी।

धनु राशि–दैनिक सफलता के साधन सम्पन्न होंगे, स्वाभाव में क्रोध व अशांति होगी।

मकर राशि–दैनिक सम्पन्नता के साधन जुटायेंगे, आलस्य, प्रमाद से हानि होगी।

कुंभ राशि–बिगड़े हुये कार्य बनेंगे, योजनायें फलीभूत होंगी, रुके कार्य बनेंगे।

मीन राशि–स्त्री वर्ग से चिन्तायें कम होंगी, विशेष कार्य स्थगित रखें, समय का ध्यान रखें।

–अम्बुजा तिवारी

विधानसभा की गरिमा और अनुशासन सर्वोपरि : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, (हि.स.)। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सत्र के आखिरी दिन सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखने की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने और विधायी कार्यवाही को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए अध्यक्ष को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।

गुप्ता ने सोमवार को रूल 277 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई सदस्य अशोभनीय या अनुशासनहीन आचरण करता है तो अध्यक्ष उसे सदन से हटने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित सदस्य को तत्काल सदन छोड़ना होगा और उस दिन की शेष कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रहना होगा।

इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी सदस्य का नाम लेने का अधिकार रखते हैं, जैसेः अध्यक्ष के निदेर्शों का पालन न करना। पूर्व में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रभावी न होना। सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित करना। एक ही सत्र में बार-बार अनुशासनहीन व्यवहार करना।

यदि किसी सदस्य का नाम लिया जाता है, तो सदन में निलंबन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, या उनके अभाव में कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। निलंबन की अवधि पहली बार तीन बैठकों के लिए, दूसरी बार सात बैठकों के लिए और तीसरी या अधिक बार झ शेष सत्र के लिए (जब तक सदन अन्यथा न निर्णय ले)।

उन्होंने कहा कि निलंबित सदस्य को तुरंत सदन के परिसर से बाहर जाना होगा। यदि वह इसका उल्लंघन करता है तो बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के पूरे सत्र के लिए निलंबन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा निलंबित सदस्य को सदन परिसर में प्रवेश करने और किसी भी विधायी या समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये प्रावधान सदन की गरिमा बनाए रखने और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से मयार्दा का पालन करने और जनहित एवं सुशासन के लिए रचनात्मक संवाद में भाग लेने का आह्वान किया।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन आरोपितों को दबोचा

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तर पश्चिमी जिले की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सिकंदराबाद निवासी साहिल (22), भलस्वा डेयरी निवासी मोहम्मद फैयाज (25) और अलीपुर निवासी दीपक (32) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है।

उत्तर पश्चिमी जिले के डीसीपी भीष्म सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 25 फरवरी को अशोक विहार थाना पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूडोकु नवताल- 7359

★★★✯✩ मध्यम

		5			8			
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6						1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
			2			7		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- *प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.*
- *प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.*
- *पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .*
- *पहेली का केवल एक ही हल है.*

सूडोकु नवताल -7358 का हल

5	7	4	1	3	9	6	2	8
2	8	9	6	5	7	1	4	3
3	6	1	2	8	4	5	7	9
9	3	7	8	1	6	4	5	2
6	5	8	4	9	2	3	1	7
1	4	2	5	7	3	8	9	6
7	9	6	3	4	1	2	8	5
4	2	5	9	6	8	7	3	1
8	1	3	7	2	5	9	6	4

दैनिक पंचांग

4 मार्च 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

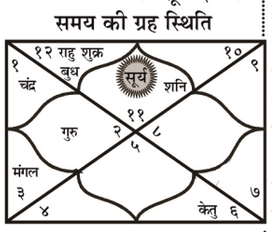

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	मीन	06.54 बजे से
चंद्र	मेष में	मेष	08.25 बजे से
मंगल	मिथुन में	वृष	10.05 बजे से
बुध	मीन में	मिथुन	12.03 बजे से
गुरु	वृष में	कर्क	14.17 बजे से
शुक्र	मीन में	सिंह	16.33 बजे से
शनि	कुंभ में	कन्या	18.45 बजे से
राहु	मीन में	तुला	20.55 बजे से
केतु	कन्या में	वृश्चिक	23.10 ब.से
राहुकाल		धनु	01.26 बजे से
3.00 से 4.30		मकर	03.31 बजे से
बजे तक		कुंभ	05.18 बजे से

मंगलवार 2025 वर्ष का 63 वा दिन
दिशाशूल उत्तर **ऋतु** शिशिर।
विक्रम संवत् 2081 **शक संवत्** 1946
मास फाल्गुन **पक्ष** शुक्ल
तिथि पंचमी 15.17 बजे को समाप्त।
नक्षत्र भरणी 02.38 बजे रात्र को समाप्त।
योग इन्द्र 02.07 बजे रात्र को समाप्त।
करण बालव 15.17 बजे तदनन्तर कौलव 02.02 बजे रात्र को समाप्त।
चन्द्रायु 04.0 घण्टे
रवि क्रान्ति दक्षिण 06° 26'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872273
जूलियन दिन 2460738.5
कलियुग संवत् 5125
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2551
हिजरी सन् 1446
महीना रमजान **तारीख** 03
विशेष स्कंद षष्ठी।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
रोग	05.53 से	07.22 बजे तक	काल	05.42 से	07.13 बजे तक
उद्वेग	07.22 से	08.15 बजे तक	लाभ	07.13 से	08.45 बजे तक
चर	08.15 से	10.19 बजे तक	उद्वेग	08.45 से	10.16 बजे तक
लाभ	10.19 से	11.48 बजे तक	शुभ	10.16 से	11.48 बजे तक
अमृत	11.48 से	01.16 बजे तक	अमृत	11.48 से	01.19 बजे तक
काल	01.16 से	02.45 बजे तक	चर	01.19 से	02.51 बजे तक
शुभ	02.45 से	04.13 बजे तक	रोग	02.51 से	04.22 बजे तक
रोग	04.13 से	05.42 बजे तक	काल	04.22 से	05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- **शुभत्व श्रेष्ठ** शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को दिल्ली विधानसभा में जाती हुईं।

शब्द पहेली - 8421

■	1		2	■	3		4	■
5		■		■		■	6	7
	■	■	8	9		10	■	
11		12	■		■	13		
■	■	14		■	15		■	■
16			■	17	■	18		19
	■	20	21		22	■	■	
23	24	■		■		■	25	
■	26			■	27			■

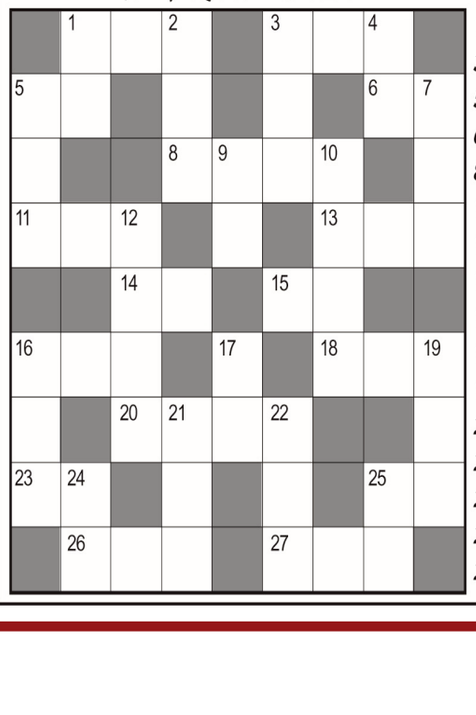

बाएँ से दाएँ

1.ईसा मसीह-3
3.जवान,तरुण-3
5.आकाश,व्योम-2
6.परत,अस्तर-2
8.गर्जना,दहाड़ना-4
11.मदद,आराम-3
13.सुगंध,खुशबू-3
14.धूल,मिट्टी-2
15.छत्तीसगढ़ की राजधानी-2
16.पिता,आविष्कारक-3
18.नस्ल,जाति,प्रजाति-3
20.ओस,रजनीजल-4
23.भीगा हुआ-2
25.बल,ताकत,दम-2
26.तेल या घी में पकाना -3
27.मसाज-3

ऊपर से नीचे

1.रसना,जिव्हा-2
2.सचेत,सावधान-3
3.जरुरत,आवश्यकता-3
4.ऋतु,मौसम-2
5.दृश्य,तमाशा-3
7.कंठ,गला-3
9.रीती,रिवाज-2
10.प्रसिद्ध,नामवर-4
12.तीर रखने का पात्र-4
16.भूमि,धरा-3
17.खदान,माईन-2
19.तरंग,हिलोर-3
21.प्रवाहित करना-3
22.भीड़,समूह-3
24.राय,वोट-2
25.उत्साह,ललक-2

शब्द पहेली -8420 का हल

■	म	ह	क	■	ता	म	झा	म
ज	न	■	म	न	न	■	■	स
हा	■	प	र	■	ना	स	■	ख
न	ज	र	बं	द	■	दा	य	रा
■	न	■	द	■	ह	■	म	■
दा	म	न	■	न	क	ब	ज	न
वा	■	ल	क	■	ब	स	■	ती
न	■	■	मा	य	का	■	ता	जा
ल	ति	या	ना	■	ना	सू	र	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

Page-03_Layout 1 3/3/2025 11:27 PM Page 1

राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खां ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी।

दोस्त ही निकला कांग्रेस नेता हिमानी का हत्यारा, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती

रोहतक, (हि.स.)। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हिमानी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके दोस्त ने की थी। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और आरोपित ने मोबाइल चार्जर की वायर (तार) से हिमानी का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव सूटकेस में डालकर सांपला बस स्टैंड के पास फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से मृतका की सोने की चैन, अंगूठी, लैपटॉप व मोबाइल फोन बरामद किया है।

जांच में यह बात भी सामने आई कि करीब एक साल पहले दोनों की सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और उसके बाद से ही दोनों में बातचीत थी। पुलिस आरोपित से आगे की पूछताछ कर रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केके राव ने बताया कि देर रात एसआईटी को सूचना मिली थी कि आरोपित दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में है। इसी आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एसआईटी ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी। पूछताछ में आरोपित की पहचान झज्जर जिले के गांव खैरपुर निवासी सचिन उर्फ ढिल्लु के रूप में हुई, जोकि झज्जर में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है। आरोपित शादी शुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि करीब एक साल पहले फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी और वह हिमानी के घर आता-जाता रहता था। घटना वाले दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हिमानी की हत्या कर दी। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। हिमानी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपित सचिन ने बताया कि उसने हिमानी के घर पर ही उसकी हत्या की और बाद में शव को सूटकेस में डालकर आटो के जरिए सांपला पहुंचा और सड़क किनारे सूटकेस को फेंक दिया। बाद में वह झज्जर स्थित अपनी दुकान पर चला गया। इसके बाद वह फरार होने की नियत से दिल्ली चला गया। एडीजीपी केके राव ने बताया कि आरोपित ने हिमानी की हत्या करने के बाद उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सोने की चैन व अंगूठी लूट ली और सारे समान को झज्जर स्थित अपनी दुकान पर रख आया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर सामान बरामद कर लिया है। अभी तक यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच पैसे का लेन-देन भी था और पुलिस इस आधार पर आरोपित से जानकारी जुटा रही है। हिमानी का शव एक मार्च को सांपला बस स्टैंड के पास सड़क किनारे सूटकेस में मिला था। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात हमलावारों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

मानवाधिकारों पर छह दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ

नई दिल्ली, (हि.स.)। वैश्विक दक्षिण के देशों में मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों में क्षमता निर्माण की छह दिवसीय कार्यशाला का आज यहां शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईईटीसी) के अन्तर्गत इसका आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ के 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) से लगभग 47 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये देश मेडागास्कर, युगांडा, समोआ, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, मॉरीशस, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और कतर हैं।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (अध्यक्ष, एनएचआरसी) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत विभिन्न जातियों, समुदायों, कला रूपों और भाषाओं के साथ समृद्ध विविध सांस्कृतिक लोकाचार का देश है और यह सदियों से साझा मूल्यों और परंपराओं की एकता में पनप रहा है। हालांकि विविधता के साथ-साथ विविध समस्याएं भी आती हैं, जिनके लिए विविध समाधानों की आवश्यकता होती है। हर देश की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परंपराएं होती हैं और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उनके साथ निपटने के लिए निर्धारित मानकीकृत दृष्टिकोणों को देखते हुए, विविधताओं को संबोधित करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि प्रत्येक देश में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ उभरती मानवाधिकार चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान करने के तरीकों पर विचार और खोज की जा सके।

उन्होंने वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई और उनके देशों के भाग लेने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने एनएचआरसी, भारत द्वारा उन्हें भागीदारी के लिए नियुक्त करने के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भी उल्लेख किया, जो देशों या सदियों में प्रचलित मानवीय मूल्यों और लोकाचारों पर प्रकाश डालते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।

न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी (सदस्य, एनएचआरसी, भारत) ने अपने भाषण में कहा कि आयोग ने अपनी व्यापक पहलों के माध्यम से भारत के मानव परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई पश्चिमी दृष्टिकोणों के विपरीत, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखते हैं, भारत एक अधिक संतुलित मॉडल का पालन करता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अधिकारों को महत्व देता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों में भारत की भागीदारी एक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसके समर्पण को दशार्ती है।

एनएचआरसी, भारत की सदस्य विजया भारती सयानी ने कहा कि अपने सामूहिक ज्ञान और संसाधनों को साझा करके हम लगातार विकसित हो रहे वैश्विक मानवाधिकार परिदृश्य के परिदृश्य में अपने राष्ट्रों और क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के कुछ प्रमुख विषयगत मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर एनएचआरसी, भारत द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता प्राप्त करना, हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा, विकास और विस्थापन के संदर्भ में कमजोर आबादी की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत पारंपरिक रूप से मानवता के व्यापक हित के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को हमेशा साझा करना चाहता है। यह प्रशिक्षण उसी भावना के साथ आयोजित किया गया है जिसमें हम एक-दूसरे से सीखने की उम्मीद और अपेक्षा करते हैं।

झारखंड विधानसभा में बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ने सौंपी मुख्यमंत्री को बजट की प्रति।

बजट में किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लोगों का रखा गया ख्याल : मुख्यमंत्री

पटना, 3 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। इस साल बिहार का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 14.5 प्रतिशत रही है।वह बिहार विधान सभा में सोमवार को पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तुत बिहार बजट (2025-26) न्याय के साथ विकास के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय संसाधनों के समुचित प्रबंधन से बिहार के आर्थिक विकास को गति देगी। सड़कों का चौड़ीकरण कर आवागमन की सुविधा को बेहतर किया जायेगा। युवाओं को रोजगार देने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हम सरकारी नौकरी के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं, इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जायेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुये विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को समावेशी, तीव्र एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बिहार बजट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जहां एक ओर हर जिले को चार लेन सड़क से जोड़ा जायेगा, वहीं राज्य के लोगों के लिये सस्ती एवं सुलभ वायु सेवा उपलब्ध कराने के लिये बजट में कई प्रावधान किये गये हैं। विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आयेगा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रही है और इस बजट में इसके लिए कई नई नीतियों के साथ बड़े और महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए गए हैं।

नीतीश कुमार कहा कि कुल मिलाकर इस बजट में किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। यह एक सम्पूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 जुलाई 2024 को केन्द्र में नई सरकार के गठन के पश्चात पेश किये गये बजट में बिहार को विशेष आर्थिक मदद दी गयी थी। पुनः एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय बजट 2025 में बिहार की विभिन्न विकास योजनाओं तथा बिहार के लोगों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की इस सहायता तथा राज्य सरकार के अपने बजटीय प्रावधानों से बिहार के विकास को और गति मिलेगी। साथ ही बिहार नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। इसके बाद आकाश आनंद की प्रतिक्रिया के बाद बसपा प्रमुख ने यह निर्णय लिया है। मायावती ने सोमवार दोपहर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रविवार को बसपा की आल-इण्डिया की बैठक में आकाश आनन्द को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोआर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लम्बी-चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वह उसके पछतावे व राजनीतिक परिपक्वता का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर-मिशनरी है।

साल 2014 के बाद रेलवे में सूचीबद्ध सभी सातों सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिला : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, (हि.स.)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने के सरकार के फैसले पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद रेलवे में सूचीबद्ध सभी सातों सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे के सभी सात सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को आज नवरत्न का दर्जा मिल गया है। यह सब 2014 के बाद हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह दशार्ता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेलवे में बदलाव लाने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब रेलवे से जुड़ा कोई संगठन मजबूत होता है, तो इसका मतलब है कि वह रेलवे के विकास में अधिक योगदान दे सकता है। रेल मंत्री ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों टीम को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई। उन्होंने कहा हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे की सभी सातों सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रम अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं और ऐसा 2014 के बाद हुआ है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) को जुलाई 2014 में नवरत्न का दर्जा दिया था। रेल विकास निगम लिमिटेड को मई 2023, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। रेल टेल को अगस्त 2024 में यह दर्जा दिया गया था। उन्होंने इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सोमवार को एक्स पोस्ट में बताया कि सरकार ने आईआरसीटीसी को नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सीपीएसई में 25वां नवरत्न बन जाएगा। आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार 4,270.18 करोड़ रुपये, पीएटी 1,111.26 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नेटवर्थ 3,229.97 करोड़ रुपये है। सरकार ने आईआरएफसी को नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सीपीएसई के बीच 26वां नवरत्न बन जाएगा। आईआरएफसी रेल मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार 26,644 करोड़ रुपये, पीएटी 6,412 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 49,178 करोड़ रुपये का नेटवर्थ है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते।

केंद्रीय खेल मंत्री ने कांग्रेस-टीएमसी पर साधा निशाना, खिलाड़ियों पर की गई टिप्पणियों को बताया शर्मनाक

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दलों को खिलाड़ियों के पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय खिलाड़ी अपने करियर को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं और राजनीतिक दलों को उन पर अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।

मनसुख मंडाविया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस और टीएमसी को खिलाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे अपने पेशेवर जीवन को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। इन दलों के कुछ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां, जिनमें बॉडी शेमिंग और खिलाड़ियों की टीम में जगह पर सवाल उठाना शामिल है, न केवल बेहद शर्मनाक हैं, बल्कि पूरी तरह निंदनीय भी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी टिप्पणियां उन खिलाड़ियों की मेहनत और त्याग का अपमान हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं। खेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर उनके मनोबल को गिराने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेल रहे हर एथलीट के सम्मान की रक्षा की जाएगी।

मंडाविया ने यह भी कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना जरूरी है। उन्होंने अपील की कि सभी राजनीतिक दल खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान करें और उनके बारे में अनावश्यक और अपमानजनक टिप्पणियों से बचें।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कांग्रेस और टीएमसी के कुछ नेताओं ने भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। कुछ नेताओं ने एक शीर्ष भारतीय खिलाड़ी के फिटनेस स्तर और टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही, कथित रूप से उनकी शारीरिक बनावट (बॉडी शेमिंग) को लेकर भी टिप्पणियां की गईं, जिससे खेल जगत में नाराजगी देखी गई। इन बयानों के बाद खेल समुदाय, पूर्व खिलाड़ी और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। इसी संदर्भ में, खेल मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और त्याग का भी अपमान करती हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की सुरक्षा में फिर चूक

चंडीगढ़, (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। सोमवार को पंचकूला में विधायकों के साथ प्री बजट बैठक करने पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी की गाड़ी के निकट एक बाइक सवार युवक आ गया। हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री गाड़ी में नहीं थे। पुलिस अधिकारियों ने जब युवक को हटने के लिए कहा तो वह उलझ गया और बहस करने लगा।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री मोदी और जैव विविधता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव दिवस पर ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आज विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। इसमें हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हमें वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व है।" प्रधानमंत्री का वन्यजीव प्रेम किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने आज अपने गृह राज्य गुजरात में विश्व वन्यजीव दिवस पर जूनागढ़ जिले में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को करीब से देखा।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डीएसएलआर कैमरे से एशियाई शेरों की तस्वीरें खींचते नजर आए। उन्होंने एक ऐसी भी तस्वीर खींची जिसमें मादा शेरनी अपने शावक को दुलारती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में एक वीडियो क्लिप भी अपलोड की। इसमें वो भारत की परंपरा में जैव विविधता के प्रति स्वाभाविक आग्रह का जिक्र कर रहे हैं। यह क्लिप 2023 की है। कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने विचार रखे थे। उन्होंने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के मन में अन्य देशों, जहां बाघों की आबादी या तो स्थिर है या फिर उसमें गिरावट हो रही है, की तुलना में भारत में बाघों की बढ़ती आबादी के बारे में उठने वाले सवालों को दोहराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "भारत इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह दोनों के सह-अस्तित्व को समान महत्व देता है।"

यहां यह महत्वपूर्ण है कि जबसे मोदी सरकार आई है तब से देश ने बाघों के संरक्षण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 2010 में भारत में करीब 1,700 बाघ थे। 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 3,600 से भी ज्यादा हो गई है। यानी सिर्फ 12 साल में बाघों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। आज, दुनिया के करीब 75 फीसद बाघ भारत में रहते हैं। यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता है और हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का पल है। यह सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से संभव हुआ है।

मोदी सरकार के कठोर प्रतिबंधों की भी इसमें बड़ी भूमिका है। सरकार ने बाघों के शिकार करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। यही नहीं, बाघों के रहने वाले जंगलों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया ताकि वह अपना जीवन बिना किसी खतरे के जी सकें। बाघों के शिकार (जैसे हिरण) की संख्या पर ध्यान दिया गया ताकि बाघों को पर्याप्त भोजन मिलता रहे। समाज को बाघों से जुड़ी जानकारी दी गई और गांवों में बाघों से जुड़े संघर्षों को कम करने के उपायों पर तेजी से काम किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी का जूनागढ़ जिले में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लेना अनायास नहीं है। दरअसल भारत में शेरों की आबादी भी बढ़ी है। वैसे भी देश में शेरों का संरक्षण सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हैं। शेरों का भारतीय मुद्रा और आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देता है। भारत एशियाई शेरों का घर है। एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों ने शेरों की आबादी को 2015 में लगभग 523 से बढ़ाकर 2020 में लगभग 674 तक पहुंचा दिया। केंद्र सरकार की 15 अगस्त, 2020 को घोषित प्रोजेक्ट लायन महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य लंबे एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

गुजरात में शेरों की संख्या और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित रूप से गणना की जाती है। इसके अलावा आग प्रबंधन, बाढ़ की तैयारी और निरंतर वन्यजीव निगरानी जैसे उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि शेरों के पास सुरक्षित आवास हों और किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान किया जाए। बड़ी बात यह है कि अप्रैल 2023 में शुरू किया गया इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस दुनिया भर में शेरों सहित बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। शेरों के इतिहास की बात करें तो वह 30 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका और यूरेशियन महाद्वीप में विचरण करते थे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी पर शेरों की उपस्थिति 30,000 से 100000 के बीच है।

जहां तक गिर वन्यजीव अभयारण्य का सवाल है तो वह एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गिर अभयारण्य 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 258 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान और 1,153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य है। पास में ही मितीयाला वन्य जीव अभयारण्य है। माना जाता है कि विश्व में अफ्रीका के बाद गिर में शेर बचे हैं। गिर के जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन के तहत 2900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। एशियाई शेर गुजरात के नौ जिलों के 53 तालुकाओं में लगभग 30 हजार वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। राष्ट्रीय परियोजना के तहत जूनागढ़ जिले के न्यू पिपल्या में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्यजीवों के चिकित्सीय निदान एवं रोगों से बचाव के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। सासण में उच्च तकनीक से युक्त निगरानी केंद्र और एक अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया है।

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वामी, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफल इंफोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।
E-mail : newdibyabharat@gmail.com

ट्रंप का टैरिफ हमला–भारत 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर खोजेगा रास्ता

वैश्विक स्तरपर कोविड -19 के बाद से दुनियाँ के हर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सी गई है, जिससे हर देश ने मेहनत कर अपने-अपने देश की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, बीच डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते व 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने के साथ ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने की क्रम बाय क्रम झड़ी सी लगा दी है, इसी क्रम में दिनांक 27 फरवरी 2025 को देर शाम यूरोपीय यूनियन पर 25 पेर्सेंट टैरिफ तथा चीन को 10 पर्सेंट और अतिरिक्त टैरिफ यानी टोटल 20 पर्सेंट टैरिफ देनी होगी। कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ 4 मार्च 2025 से लागू करने की बात कही गई है। असल में ट्रंप का अमेरिकी फर्स्ट के लिए हर सक्षम उपाय करने में तेजी से आगे बढ़ गए हैं, ताकि अमेरिका को अधिक से अधिक आय हो जिससे वह अपने कर्ज को कम करके धीरे-धीरे जीरो टॉलरेंस पर ले जाकर अर्थव्यवस्था में नई जान फूँकने पर आतुर है जिसका सटीक उदाहरण, बढ़ते टैरिफ की संभावना से पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। उपभोक्ता आशंका जता रहे हैं थे कि अगर अमेरिका के दो बड़े व्यापिरक साझेदार कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है और ऑटो क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। और हुआ भी वही 4 मार्च 2025 से 25 पर्सेंट टैक्स रखना शुरू हो जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत स्तरपर मानना है कि अपने देश के नागरिकों को प्राथमिकता देना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कड़े कदम उठाना अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक कीमत चुकाने के लिए हर देश को रणनीति रूप से तैयार रहना चाहिए। कुछ हद तक इसका संज्ञान ट्रंप से लिया जा सकता है, चूँकि ट्रंप का टैरिफ हमला, भारत 27 देशो के यूरोपियन यूनियन संगठन सहित दुनियाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना समय की मांग है तथा ट्रंप का टैरिफ हमला, भारत 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर रास्ता खोजेगा इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से व इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक से दुनियाँ में हलचल यूरोपीय यूनियन कनाडा, चीन मैक्सिको सहित अनेक देशों पर टैरिफ अटैक, 4 मार्च 2025 से लागू होंगे।

साथियों बात अगर हम ट्रंप के टैरिफ अटैक की करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिका की नागरिकता हासिल करने का सीधा रास्ता खोल दिया है। उन्होंने बुधवार को नए प्रवासन कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि लोग 50 लाख डॉलर अथवा 43.7 करोड़ रुपये देकर उनके देश में रहने का सपना साकार कर सकते हैं। नए कार्यक्रम के तहत जारी होने वाला गोल्ड कार्ड पुराने रोजगार आधारित ईबी-5 वीजा की जगह लेगा। नई व्यवस्था से उन भारतीयों को तगड़ा झटका लगा है जो अमेरिका में रहने के लिए ईबी-5 वीजा को एच-1बी वीजा के विकल्प के तौर पर देख रहे थे। वह अगले मंगलवार से मैक्सिको और कनाडा पर कर (टैरिफ) लगाएंगे, साथ ही चीन से आयात पर मौजूदा10 फीसदी टैरिफ दोगुना करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फेंटेनाइल जैसी नशीली दवाओं की अमेरिका में अस्वीकार्य स्तर पर तस्करी की जा रही है और आयात कर अन्य देशकों को तस्करी पर रोक लगाने के लिए मजबूर करेंगे। ट्रंप ने लिखा, हम इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए जब तक यह बंद नहीं हो जाता है या गंभीर रूप से सीमित नहीं हो जाता है, प्रस्तावित टैरिफ (जो चार मार्च से लागू होने वाले हैं) तय कार्यक्रम के अनुसार प्रभावी होंगे। उस तारीख पर चीन पर भी उसी दिन 10 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा।

साथियों बात अगर हम ट्रंप के डायरेक्ट टैरिफ अटैक पर दुनियाँ की नाराजगी जताने की करें तो, कई स्वास्थ्य समूहों और गैर- सरकारी संगठनों ने यूएसए आईडी की फंडिंग में कटौती करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर हैरानी और नाराजगी व नाराजगी जताई। इन संगठनों ने कहा कि इस फैसले के बाद कई मानवीय कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। एक महीने पहले ट्रंप ने यूएसए आईडी की फंडिंग की 90 दिनों तक समीक्षा करने की घोषणा की थी। यह फैसला उन पहलों को बंद कर देगा जो दुनियाँ भर में भूख और बीमारी से लड़ने वाले लाखों लोगों के जीवन को बचाते हैं। दुनियाँ भर में सहायता कार्यक्रमों पर काम करने वाले अमेरिकी एनजीओ का एक समूह इंटरएक्शन ने कहा, ट्रंप के फैसले से महिलाएं और बच्चे भूखे रहेंगे, गोदामों में रखा भोजन सड़ जाएगा,जबकि कई परिवार भूख से मरेंगे और बच्चे एचआईवी के साथ पैदा होंगे। यह अनावश्यक फैसला अमेरिका को सुरक्षित, मजबूत या अधिक समृद्ध नहीं बनाएगा। इसके बजाय, यह अस्थिरता, प्रवास और निराशा को निश्चित रूप से जन्म देगी। साथियों बात अगर हम ट्रंप द्वारा यूरोपियन यूनियन पर 25 प्रतिशत टैक्स लगाने की करेंतो, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कई देशों पर टैरिफ लगा चुके ट्रम्प ने अब यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने की बात कही है। उन्होंने ऐलान किया है कि यूरोपियन यूनियन के उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ होगा। जिसमें ऑटो और अन्य सामान भी शामिल हैं ।ट्रम्प ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका को परेशान करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा,हम बहुत जल्द इसकी (टैरिफ की) घोषणा करेंगे। और यह कारों और अन्य सभी चीजों पर लागू होगा। ट्रम्प ने कहा कि यूरोप के साथ व्यापार भी उनकी नजर में है और यूरोपीय नीतियों के कारण अमेरिकी खाद्य उत्पादों और कारों के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। अमेरिका को परेशान करने का यही इसका उद्देश्य है और उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन अब मैं राष्ट्रपति हूं,हम जल्द ही प्रतिशोधी टैरिफ लगाएंगे क्योंकि इसका अर्थ है कि यदि वे हम पर शुल्क लगाते हैं, तो हम भी उन पर टैरिफ लगाएंगे। यह बहुत सरल है। कोई भी देश, चाहे भारत हो, चीन हो या कोई अन्य, जो भी टैरिफ हम पर लगाते हैं, हम भी उसी रेशियो में उन पर टैरिफ लगाएंगे। हम निष्पक्षता चाहते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनका प्रशासन जल्द ही भारत और चीन जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा यह घोषणा उन्होंने वाणिज्य सचिव के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह निर्णय भारतीय पीएम की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भी चर्चा में था।

साथियों बात अगर हम यूरोपियन यूनियन नें भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना जरूरी होने, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष की 27 फरवरी 2024 को भारत पहुंचने की करें तो, ईयू भारत का बड़ा व्यापारिक दोस्त है, 2023 में 12.2 पर्सेंट व्यापार हुआ. दोनों एफटीए पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा में भी मदद, जैसे समुद्र और तकनीक में, आईएमसीई से व्यापार आसान होगा यूरोपीय संघ (ईयू) की प्रमुख उसुर्ला वॉन डेर लेयेन गुरुवार को भारत पहुंचीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत आने के बाद यूरोपीय संघ की प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि संघर्ष और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में भरोसेमंद मित्रों कीजरूरत होती है और यूरोप के लिए भारत एक ऐसा ही मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के कॉलेज ऑफ कमिश्नर यानी वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को भारत पहुंचा,जिनकी शुक्रवार को पीएम के साथ मुलाकात हुई । इसमें भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत होने की उम्मीद हैं। उसुर्ला लेयेन ने साफ किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप को भारत में एक भरोसेमंद मित्र नजर आ रहा है। मैं भारतीय पीएम के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी कि हमारी रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर कैसे ले जाया जाए। व्यापक वार्ता में लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मजबूत करने और रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों पक्ष रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत- प्रशांत की स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श कर सकते हैं, व एक संयुक्त वक्तव्य जारी होने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईयू के साथ साझेदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम व्यापार और रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ ठोस प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच एफटीए पर विचार-विमर्श की उम्मीद है क्योंकि हमें जल्द से जल्द एक पारस्परिक लाभकारी सौदे की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ अपनी तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार में अनुचित बाधाओं के खिलाफ दृढ़ता से और तुरंत प्रतिक्रिया देने की बात कह चुका है। दोनों पक्षों का मानना है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक जुड़ाव को काफी हद तक बढ़ाएगा। उनके मुताबिक, यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत कारों, शराब और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करे और भारत को भी ईयू से कुछ अपेक्षाएं हैं। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विस्तार के तरीकों की भी तलाश करेंगे। अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष सूचना सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। इससे रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार होगी। रक्षा संबंधों को बढ़ाने के क्रम में यूरोपीय संघ की तरफ से जल्द ही भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी -आईओआर) में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की उम्मीद है ।वस्तुओं की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें यूरोपीय संघ को निर्यात 76 बिलियन डॉलर और वहां से आयात 59 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। इस तरह से भारत वस्तुओं के मामले में उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 में सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 53 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें 30 बिलियन डॉलर का भारतीय निर्यात और 23 बिलियन डॉलर का आयात शामिल है, जो सेवाओं में अब तक का सबसे अधिक व्यापार है ।भारत में करीब छह हजार यूरोपीय कंपनियां ।भारत में यूरोपीय संघ के निवेश का मूल्य 117 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां भारत में मौजूद हैं। यूरोपीय संघ में भारत का निवेश लगभग 40 बिलियन डॉलर है। दोनों पक्ष 2021 में शुरू की गई भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी उत्सुक हैं। साझेदारी ने तीसरे देशों सहित कनेक्टिविटी पर सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को भी रेखांकित किया।

अतः उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययनकर इसका विशेष करें करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ अटैक से दुनिया में हलचल- यूरोपीय यूनियन, कनाडा, चीन, मैक्सिको सहित अनेक देशों पर टैरिफ अटैक- 4 मार्च 2025 से लागू होंगे ।ट्रंप का टैरिफ हमला- भारत 27 देश के संगठन यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर खोजेगा रास्ता भारत का यूरोपीय यूनियन सहित अनेक देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना समय की मांग।

प्राण त्याग कर दे गए राष्ट्र भक्ति का संदेश

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी और विचारक लाला हरदयाल की गणना उन विरले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में होती है जिन्होंने केवल भारत ही नहीं अपितु अमेरिका और लंदन में भी अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जनमत जगाया। लालाजी को अपने पक्ष में करने के लिये अंग्रेजों ने बहुत प्रलोभन दिए। उस समय की सबसे प्रतिष्ठित आईसीएस पद के प्रस्ताव भी दिया था जिसे लालाजी ने ठुकरा दिया था। यही आईसीएस सेवा को अब आईएएस के रूप में जाना जाता है। ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्र भक्त लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। उनका पैतृक घर दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित था। यह गुरुद्वारा शीशगंज उसी स्थल पर बना है जहां औरंगजेब की कठोर यातनाओं से गुरु तेगबहादुर जी का बलिदान हुआ था। लाला जी के पिता पं गोरेलाल जी संस्कृत के विद्वान और कोर्ट में रीडर थे। माता भोलारानी रामचरित मानस की विदुषी मानी जाती थीं। उनका परिवार आर्य समाज से जुड़ा था। इस प्रकार घर और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना का वातावरण था। इसी वातावरण में लाला हरदयाल का जन्म हुआ था।

परिवार के संस्कारों ने उन्हें बचपन से राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कर दिया था। उन्हें बचपन में मां से रामायण की और पिता से संस्कृत शिक्षा मिली। उन्हें रामायण की चौपाइयां और संस्कृत के अनेक श्लोक कंठस्थ थे। उन दिनों के सभी शासकीय विद्यालयों में चर्च का नियंत्रण हुआ करता था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई और महाविद्यालयीन शिक्षा सेन्ट स्टीफन कालेज में। वे पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे। सदैव प्रथम ही आते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार सुनकर पूरा पाठ कंठस्थ हो जाता था। उनकी गणना ऐसे विरले व्यक्तियों में होती थी जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाएं धारा प्रवाह बोल लेते थे। इस विशेषता ने उन्हें पूरे महाविद्यालय में लोकप्रिय बना दिया था। वे महाविद्यालयीन शिक्षा में कालेज में टाप पर रहने से उन्हे 200 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। इस राशि से वे आगे पढ़ने के लिये लंदन गए। 1905 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लालाजी ने लंदन में भारतीयों के साथ अंग्रेजों का हीनता से भरा व्यवहार देखा जिससे वे बहुत विचलित हुए। यद्यपि इसका आभास उन्हें दिल्ली के सेन्ट स्टीफन कालेज में भी हो गया था। पर जो दृश्य लंदन में देखा उसे देखकर बहुत विचलित हुए और उन्होने अपने छात्र जीवन में जाग्रति और वैचारिक संगठन का अभियान आरंभ कर दिया। भारतीय छात्रों में संगठन और जाग्रति के लिये उन्होंने संगोष्ठियों और बैठकों का कार्य आरंभ किया।

वे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते थे जिनमें भारतीय चिंतन की प्रतिष्ठा गरिमा और ओज के साथ हो संगठनात्मक भाव भी जाग्रत हो। लाला जी लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे मास्टर अमीरचंद के संपर्क में आये। उनका संपर्क क्रातिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी हुआ। श्याम कृष्ण जी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लालाजी उसके सदस्य बन गए। क्रान्तिकारियों के संपर्क और अध्ययन से लालाजी को यह भी आभास हुआ कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का दबदबा भारतीय सैनिकों के कारण है। जहां कभी भी सेना भेजना होती वहां सबसे अधिक सैनिकों की संख्या भारतीय मूल के सैनिकों की होती लेकिन अंग्रेज उनसे सम्मान जनक व्यवहार नहीं करते थे। उनकी कुशाग्रता और सक्रियता अंग्रेजों से छुपी न रह सकी उन्हे 1906 में आईसीएस सेवा का प्रस्ताव मिला जिसे ठुकराकर वे लंदन में भारतीयों के संगठन और स्वाभिमान जागरण के अभियान में ही लगे रहे।

उन दिनों चर्च और मिशनरियों ने युवाओं को जोड़ने के लिये एक संस्था बना रखी थी उसका नाम यंग मैन क्रिश्चियन एसोशियेशन था। इसे संक्षिप्त में वायएमसीए कहा जाता था। इसकी शाखायें भारत में भी थीं लाला हरदयाल जी ने भारतीय युवकों में चेतना जगाने के लिये क्रान्तिकारियों की एक संस्था यंगमैन इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। उनकी सक्रियता देख उन पर स्थानीय प्रशासन का दबाब बना। वे 1908 में भारत लौट आए। यहां आकर भी वे युवकों के संगठन में ही लग गए। उनका अभियान था कि भारतीय युवक ब्रिटिश शासन और सेना की मजबूती में कोई सहायता न करें। इसके लिए उन्होंने देश व्यापी यात्रा की। लोकमान्य तिलक से मिले। उन्होंने लाहौर जाकर एक अंग्रेजी में समाचार पत्र आरंभ किया। उनका समाचार पत्र राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ था। अंग्रेजों ने समाचार पत्र के एक समाचार के बहाने उनपर एक मुकदमा दर्ज किया। इसकी खबर उन्हें लग गई और वे अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर गदर पार्टी की स्थापना की।

उन्होंने कनाडा और अमेरिका में घूम-घूम कर वहां निवासी भारतीयों को स्वयं के गौरव और भारत की स्वतंत्रता के लिये जागरूक किया। तभी काकोरी कांड के षडयंत्र कारियों में उनका भी नाम आया। अंग्रेजों ने उन्हे भारत लाने के प्रयास किए। पहले तो अमेरिकी सरकार ने अनुमति नहीं दी। लेकिन बाद में 1938 अनुमति दे दी गई। उन्हें 1939 भारत लाया जा रहा था कि रास्ते में फिलाडेल्फिया में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। आशंका है कि उन्हें मार्ग में विष दिया गया। जब उनकी मृत्यु हुई तब वे भोजन कर रहे थे। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। वे पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कैसे भोजन करते करते शरीर त्याग सकता है। वह 4 मार्च 1939 का दिन था जब लाला जी इस नश्वर संसार को त्याग कर परम ज्योति में विलीन हो गए , पर इतिहास के पन्नों में राष्ट्र भक्ति का संदेश दे गए।

–रमेश शर्मा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं।)

कैंसर रोधी वैक्सीन कितनी कारगर, अभी बहुत कुछ शोध होना शेष

राकेश दुबेरूस ने घोषणा की है कि उसने कैंसर की रोकथाम के लिए एक नई एमआरएनए-आधारित वैक्सीन विकसित की है जो जल्द ही रोगियों को मुफ्त उपलब्ध करायी जाएगी। गमालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलोजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक एलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग के मुतसबिक, इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स से मालूम हुआ है कि यह रसौली को बढ़ने से रोकती है और उसके आशंकित रूप-परिवर्तन को भी। एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वह जेनेटिक सूचना उपलब्ध कराती है, जो शरीर की कोशिकाओं को एंटीजन (प्रोटीन या अन्य पदार्थ जो प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया आरंभ करता है) उत्पादन करना सिखाती है। जब यह एंटीजन कैंसर कोशिकाओं पर पहचान लिए जाते हैं तो इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ हमला शुरू कर देता है ।प्रश्न यह है कि यह वैक्सीन किस तरह से काम करती है? दरअसल, एमआरएनए कैंसर वैक्सीन इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है। कैंसर कोशिकाएं अक्सर ऐसा तरीका विकसित कर लेती हैं कि वह पहचान में आने से बच जायें फलस्वरूप प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। इस बचाव के तरीके को अब समझ लिया गया है और इम्यूनोथेरेपी का विचार यह है कि शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को इस प्रकार मजबूत कर दिया जाये कि वह कैंसर कोशिकाओं को तलाश करके उन्हें नष्ट कर दे तथा फैलने से रोके। इस उपचार में कीमोथेरेपी के विपरीत केवल कैंसर कोशिकाओं को ही नष्ट किया जाता है, नतीजतन साइड-इफेक्ट्स कम हो जाते हैं ।वैक्सीन के अतिरिक्त भी इम्यूनोथेरेपी के अन्य अनेक तरीके हैं जैसे कार टी सेल थेरेपी, इम्यून चेकपॉइंट इन्हिबिटर्स आदि। अन्य वैक्सीनों की तरह एमआरएनए कैंसर वैक्सीन रोग को रोकने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं है कि टीकाकरण करा लिया और रोग होगा ही नहीं। इन्हें उन रोगियों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पहले से ही कैंसर है ताकि रसौली को निशाना बनाकर उसका उपचार किया जा सके। यह उपचार विधि इस तरह से तैयार की गई है कि हर रोगी की रसौली में जो विशिष्ट एंटीजन होते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाये, जिससे यह वैक्सीन व्यक्तिगत हो जाती है और अधिक प्रभावी भी। कैंसर एमआरएनए वैक्सीन को इस तरह से भी डिजाइन किया जा सकता है कि अनेक प्रकार के एंटीजन को निशाना बनाया जा सके ।कैंसर की वैक्सीन का शोध केवल रूस में ही नहीं हुआ है। पिछले साल इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस ने कैंसर वैक्सीन लांच पैड स्थापित किया, जो एक ट्रायल कार्यक्रम है ताकि एमआरएनए व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में उन लोगों के लिए तेजी लायी जा सके, जिनको कैंसर होने की पुष्टि हो चुकी है और साथ ही कैंसर का उपचार करने के लिए कैंसर वैक्सीन के विकास को गति प्रदान की जा सके। अमेरिका में ग्लोबल बायोफर्मास्यूटिकल कंपनी क्योरवैक ने पिछले सितम्बर में घोषणा की कि सीवीजीबीएम कैंसर वैक्सीन ने ग्लिओबलस्टोमा (ब्रेन कैंसर) रोगियों पर पहले चरण के अध्ययन में उत्सावर्धक प्रतिरोधात्मक (इम्यून) प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित की हैं। वर्तमान में कैंसर वैक्सीन को लेकर संसार के विभिन्न हिस्सों में 120 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन शब्द का प्रयोग भ्रामक है ।जहां तक कैंसर के रोकथाम की बात है तो ह्यूमन पपीलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस सिलसिले में 90 प्रतिशत से अधिक केस इस वायरस के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी वायरल संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती है, उसकी भी जिगर के कैंसर को रोकने में सुरक्षात्मक भूमिका हो सकती है। डॉक्टर इस बात पर बल देते हैं, " इम्यूनोथेरेपी उपचार से कैंसर को होने से नहीं रोका जा सकता। यह रोग होने के बाद का इलाज है।" कोई भी नई ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स के अनेक चरणों से गुजरती है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। जब तक यह सब डाटा सार्वजनिक तौरपर उपलब्ध नहीं होता है, तब तक यह कहना कठिन है कि रूस की उपचार विधि किस स्तर पर है और वह कितनी सुरक्षित व प्रभावी है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

Page-05_Layout 1 3/4/2025 1:42 AM Page 1

उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र को सम्बोधित किया।

उपायुक्त गंदेरबल ने जिला कौशल समिति की बैठक की अध्यक्षता की

दिव्य भारत संवाददाता

गंदेरबल। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) गंदेरबल, जतिन किशोर ने आज वीसी रूम, डीसी ऑफिस, गंदेरबल में जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) की तैयारी की समीक्षा के लिए जिला कौशल समिति (डीएससी) की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जिले में किए गए कौशल विकास पहलों का मूल्यांकन किया गया और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए व्यावसायिक और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण को बढ़ाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक का मुख्य फोकस संकल्प के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) था, जिसे जेकेईडीआई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का समर्थन करना है।

जिला नोडल अधिकारी, जेकेईडीआई ने समिति को सूचित किया कि कार्यक्रम प्रतिभागियों को एक कैरियर के रूप में उद्यमिता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और एक उद्यम शुरू करने और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएगा।

डीसी ने अधिकारियों को जिले में कौशल की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों में बेरोजगार युवाओं का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि जिले में बेरोजगारी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कौशल विकास पहलों के दायरे का विस्तार करने के लिए विभिन्न लाइन विभागों को शामिल करते हुए एक व्यापक जिला कौशल योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे जिले के युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, महाप्रबंधक डीआईसी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी और अन्य समिति के सदस्य शामिल हुए।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री और विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने आज बजट सत्र के लिए बैठक की और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, अन्य पूर्व सांसदों और विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनका पिछले सत्र के बाद निधन हो गया। श्रद्धांजलि के दौरान, अध्यक्ष ने देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। उन्होंने उन्हें एक राजनेता के रूप में याद किया, जिनका इस राष्ट्र के लिए योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सैयद गुलाम हुसैन गिलानी, पूर्व सांसद शमशेर सिंह मन्हास, पूर्व विधायक गुलाम हसन परे और चौधरी पैरा सिंह को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान विधायक मुबारक गुल, शाम लाल शर्मा, डॉ. नरिंदर सिंह, डॉ. बशीर अहमद शाह वीरी, गुलाम अहमद मीर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अब्दुल मजीद लारमी, मोहम्मद रफीक नाइकू, विक्रम रंधावा, निजामुद्दीन भट, सतीश कुमार शर्मा और इफ्तिखार अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अन्य पूर्व सांसदों और विधायकों को श्रद्धांजलि दी, जिनका निधन पिछले सत्र के बाद हुआ। स्पीकर और सदन के सदस्यों ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा।

भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), जम्मू-कश्मीर यूटी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. एमए अलीम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की।

जम्मू संस्कृति स्कूल का प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल से मिला

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। जम्मू संस्कृति स्कूल के प्रबंधन दल के सदस्यों ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्पित एक उन्नत स्कूल स्थापित करने की स्कूल प्रबंधन की भविष्य की योजना के बारे में जानकारी दी।

उपायुक्त पुंछ ने भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। उपायुक्त पुंछ, विकास कुंडल ने एक बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) से संबंधित कई मामलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान, डीसी ने सीएलयू मामलों को संसाधित करने में संबंधित विभागों के प्रदर्शन का आकलन किया। कुल 10 मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें से 1 मामले को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, 6 मामलों को वापस कर दिया गया, और नीतियों के अनुपालन पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद 3 मामलों को खारिज कर दिया गया। समय पर एनओसी जारी करने के महत्व पर जोर देते हुए, डीसी ने सदस्यों को दस्तावेजों का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएलयू आवेदनों को संसाधित करते समय स्थापित दिशानिदेर्शों और नीतियों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को दोहराया, जिसका उद्देश्य भविष्य के आवेदनों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

जम्मू केन्द्रीय सहकारी बैंक के एमडी ने बैंक की भौतिक, वित्तीय प्रगति की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। जम्मू केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बाल कृष्ण ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जम्मू के साथ सोमवार को बैंक की 85 शाखाओं की व्यापक शाखावार समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए), जमा, ऋण और अग्रिम, विभिन्न वित्तीय अनुपात, हानि प्रतिशत को कम करने के उपाय और वसूली में वृद्धि शामिल हैं। प्रबंध निदेशक ने शाखा प्रमुखों से मासिक आधार पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को सहकारी विभाग के अधिकारियों की मदद से राशि की वसूली के लिए शिविर आयोजित करने और सहकारी बैंक के लाभों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रबंध निदेशक ने सभी शाखा प्रमुखों से सीडी अनुपात को बढ़ाने और मजबूत वसूली रणनीतियों और बेहतर बैंकिंग सेवाओं के वितरण के माध्यम से एनपीए को कम करने का आग्रह किया। बैठक में बैंक के कार्यकारी प्रबंधक परमजीत सिंह सलाथिया, उप कार्यकारी प्रबंधक रीता शर्मा, सहायक कार्यकारी प्रबंधक सोनल बख्शी, सुनील शर्मा तथा बैंक के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने करनाह से गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया

दिव्य भारत संवाददाता

कुपवाड़ा। हाल ही में भारी बर्फबारी के कारण जिले में विभिन्न सीमा सड़कों के बंद होने के बाद, जिला प्रशासन कुपवाड़ा ने बर्फ से घिरे सीमावर्ती क्षेत्र करनाह से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया, ताकि उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल मिल सके।

कुपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर (डीसी), आयुषी सूदन के निदेर्शों पर, अधिकारियों और फील्ड स्टाफ द्वारा एक निकासी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान खारवापरा से 15 वर्षीय रोहेल मीर और कोना गबरा से 18 महीने की बीबी सना, दोनों को तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, उन्हें करनाह से एयरलिफ्ट किया गया। कुपवाड़ा में उनके सुरक्षित निकासी के बाद, दोनों रोगियों को उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए श्रीनगर पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में सवार किया गया।

जिले भर में हाल ही में बर्फबारी के बाद करनाह, माछिल और केरन की विभिन्न सीमा सड़कें बंद हो गई जिला मुख्यालय से विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्बाध हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित करने के लिए सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) को सेवा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बीच, करनाह क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सक्रिय दृष्टिकोण के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का आभार व्यक्त किया है।

उपायुक्त शोपियां ने मुगल रोड खोलने पर बैठक बुलाई

दिव्य भारत संवाददाता

शोपियां। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शिशिर गुप्ता ने आज मुगल रोड को वाहनों के लिए खोलने के संबंध में अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। डीसी ने मुगल रोड को नियमित यातायात के लिए खोलने की व्यवहार्यता के बारे में जानकारी ली। बीआरओ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अधिकारियों ने पीर पंजाल के पार महत्वपूर्ण सड़क संपर्क के साथ बर्फ हटाने के कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण मुगल रोड को खोलने में देरी हुई है, क्योंकि बर्फ हटाने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ी है। डीसी ने सड़क के महत्व पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त मशीनरी की तैनाती के साथ बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि इसे जल्द ही यातायात के लिए खोला जा सके।

उपायुक्त कुपवाड़ा ने शिक्षा सहायता योजना के तहत भुगतान के लिए 3.50 करोड़ रुपये का चेक सौंपा

दिव्य भारत संवाददाता

कुपवाड़ा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, आयुषी सूदन ने आज शिक्षा सहायता योजना के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को भुगतान के लिए जेएंडके बैंक को 3.50 करोड़ रुपये का चेक सौंपा।

इस अवसर पर बोलते हुए, डीसी ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रम लाभार्थियों की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर उपस्थित सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) कुपवाड़ा ने विवरण देते हुए बताया कि शिक्षा सहायता योजना के तहत 3.50 करोड़ रुपये की राशि जिले के 8027 श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए जमा की जाएगी।

उपायुक्त कुपवाड़ा ने शिक्षा सहायता योजना के तहत भुगतान के लिए 3.50 करोड़ रुपये का चेक सौंपा।

जम्मू-कश्मीर ने एशिया-प्रशांत में 12वें क्षेत्रीय 3आर, सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में संधारणीय नवाचारों का प्रदर्शन किया

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। एक ऐतिहासिक कदम में, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2030 तक श्रीनगर को जीरो-लैंडफिल शहर में बदलने के लिए स्मार्ट संग्रह नेटवर्क और एआई-संचालित रीसाइक्लिंग हब सहित एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के संबंध में उक्कक्कर 2.0 कार्यक्रम के तहत एक समझौता ज्ञापन (टङ्कव) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन 3 से 5 मार्च, 2025 तक राजस्थान में आयोजित एशिया और प्रशांत में 12वें क्षेत्रीय 3आर (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल) और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। इसके अतिरिक्त, यूटी सरकार ने उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली संस्था, जलवायु वेधशाला स्थापित करने के लिए एक राज्य-स्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। वेधशाला जलवायु चरों की निगरानी करेगी, जोखिमों का आकलन करेगी और कृषि, पर्यटन और जल संसाधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अनुकूली रणनीति तैयार करेगी।

यह आयोजन सतत विकास और संसाधन दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच है, जिसमें जम्मू-कश्मीर ने अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं में अपनी अग्रणी पहलों को उजागर किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण (एलसीएमए) ने फोरम में जम्मू-कश्मीर की अभूतपूर्व डल झील खरपतवार प्रसंस्करण इकाई का प्रदर्शन किया, जिसने नीति निमार्ताओं, टेक्नोक्रेट और स्थिरता विशेषज्ञों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया। यह परियोजना, जो आक्रामक जलीय खरपतवारों को जैविक खाद और बायोगैस में परिवर्तित करती है, परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए यूटी के अभिनव दृष्टिकोण का उदाहरण है।

देश भर से नीति निमार्ताओं, विचारकों, शोधकर्ताओं और योजनाकारों सहित गणमान्य व्यक्तियों ने जम्मू-कश्मीर के स्टॉल का दौरा किया और झील के कचरे को मूल्यवान संसाधनों में बदलने की पहल की सराहना की, जिसमें टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया गया।

आवास और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर प्रतिनिधिमंडल ने अन्य राज्यों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक ज्ञान-साझाकरण सत्रों में भाग लिया। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में अपशिष्ट से अद्भुत प्रौद्योगिकियां, अपशिष्ट से ऊर्जा नवाचार और समुदाय के नेतृत्व वाली परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल शामिल थे। फोरम ने विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विचारों का खजाना पेश किया।

इस यात्रा ने जम्मू और कश्मीर में संभावित प्रतिकृति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और आधुनिक तकनीकों का पता लगाने का अवसर प्रदान किया। फोरम में जम्मू और कश्मीर की भागीदारी टिकाऊ शहरी विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो पर्यावरण संरक्षण और संसाधन दक्षता के व्यापक दृष्टिकोण के साथ सरेखित है। प्रासंगिक रूप से, उक्कक्कर 2.0 एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाली एक प्रमुख पहल है देश के 14 राज्यों के 18 शहरों को लाभ पहुंचाने के लिए 1800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को चुना गया। 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आने वाले दिनों में जारी रहेगा, जिसमें देश में सतत शहरी विकास और सर्कुलरिटी के भविष्य को आकार देने के उद्देश्य से विशेषज्ञ चचार्एं, नीतिगत संवाद और सहयोगात्मक पहल शामिल होंगी।

जम्मू-कश्मीर ने एशिया-प्रशांत में 12वें क्षेत्रीय 3आर, सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में संधारणीय नवाचारों का प्रदर्शन किया।

उपायुक्त बांदीपोरा ने कार्यों के निष्पादन और कार्य योजना की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

बांदीपोरा। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) बांदीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएचपीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत चल रहे कार्यों और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किशनगंगा परियोजना के तहत एनएचपीसी की सीएसआर पहलों के निष्पादन और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजनाओं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सीएसआर कार्यों के लिए 92.08 लाख रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 155.67 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

डीसी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित लंबित 10% धनराशि जारी करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा 10 मार्च, 2025 तक आवंटित धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने के महत्व पर बल दिया। पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डीसी ने संबंधित विभागों को उचित क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन गतिविधियों के लिए एक विस्तृत स्थान योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की सीएसआर गतिविधियों की तैयारी में, कादरी ने संबंधित विभागों से सामुदायिक लाभ और प्रभाव क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियों की पहचान करने का आग्रह किया।

Page-06_Layout 1 3/3/2025 11:26 PM Page 1

खारकीव में रुसी ड्रोन हमले के बाद एक इमारत में लगी आग बुझाते हुए दमकलकर्मी।

नेपाल में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने किया अध्यादेश और विधेयक का विरोध

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार लाए गए छह अध्यादेशों और तीन विधेयकों पर फंसती नजर आ रही है। सरकार में शामिल सबसे बड़े घटक दल नेपाली कांग्रेस के नेता खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। अध्यादेश एक माह होने के बाद भी संसद में पेश नहीं किया जा सके हैं। अगर अगले 30 दिनों में इनको संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं कराया गया तो ये स्वतः खारिज हो जाएंगे। इन अध्यादेश का सरकार को बाहर से समर्थन दे रही जनता समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन नहीं करने का फैसला कर लिया है। इस वजह से ऊपरी सदन में सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई है। तीन विधेयकों का भी सत्तारूढ़ घटक दल नेपाली कांग्रेस विरोध कर रही है। इनमें सोशल मीडिया को नियंत्रण करने के लिए लाया गया विधेयक, सुरक्षा बलों के मर्जर संबंदी विधेयक और सशस्त्र प्रहरी बल से संबंधी विधेयक शामिल है। ओली सरकार में शामिल गृहमंत्री नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक हैं। उनकी पार्टी का एक बड़ा गुट इन विधेयकों के खिलाफ बोलने लगा है। पिछले दो दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ सरकार के खिलाफ और इन विधेयकों के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया है। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि ओली सरकार ने विधेयक लाने में मनमानी की है। ओली दाएं-बाएं करेंगे तो समर्थन वापसी पर विचार करना होगा। थापा ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया बिल से लेकर सिक्योरिटी संबंधी बिल लाया गया है उसमें बदलाव किए बिना पारित नहीं कराया जा सकता। पोखरा में आज आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेशमंत्री एनपी साउद ने कहा कि सरकार को दो तिहाई का दंभ दिखाना बंद करना चाहिए। सुरक्षाबलों से संबंधित बिल इसी दंभ के कारण लाया गया है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बालकृष्ण खांड ने रविवार को भैरहवा में कहा कि गठबंधन अपने मूल उद्देश्य से भटक कर विवादास्पद विषयों पर विधेयक ला रहा है। नेपाली कांग्रेस इस देश की सभी बड़ी पार्टी है। खांड ने आरोप लगाया कि ओली अपनी नीतियां कांग्रेस पर थोप रहे हैं।

पाकिस्तान में अवैध रूप से रखे गए काले भालू को मुक्त कराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में अवैध रूप से रखे गए एक काले भालू को मुक्त कराया गया जिसे उपचार के लिए इस्लामाबाद लाया गया है। पशु कल्याण से जुड़े एक संगठन ने इसकी जानकारी दी। सात वर्षीय भालू को पंजाब प्रांत में अवैध रूप से रखा गया था। स्थानीय अधिकारियों ने भालू को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हस्तक्षेप किया।

शेख हसीना के शासन में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों का लेखा-जोखा तैयार करना जरूरी : यूनुस

ढाका, (हि.स.)। बांग्लादेश की अंतरिम सलाहकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूनुस की टिप्पणी रविवार को संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ग्विन लुईस और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक कार्यालय की वरिष्ठ मानवाधिकार सलाहकार हुमा खान के साथ चर्चा के दौरान आई। यह मुलाकात राज्य अतिथि गृह जमुना में हुई। ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार उन्होंने शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई, डेलवर हुसैन सईदी के खिलाफ फैसले के बाद पुलिस की बर्बरता और वर्षों में गैर-न्यायिक हत्याओं जैसी घटनाओं की विशेष रूप से चर्चा की। यूनुस ने कहा कि देश के लोगों के खिलाफ किए गए सभी तरह के अत्याचारों के उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। जब तक यह दस्तावेज तैयार नहीं हो जाता, न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल है। लुईस ने उन्हें आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश को इन उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने की क्षमता बनाने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यूनुस ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट प्रकाशित की है।

लुईस ने मुख्य सलाहकार को बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क पांच मार्च को मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान सदस्य देशों को रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में जानकारी देंगे।

उन्होंने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा रोहिंग्या संकट पर नए सिरे से वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगी। लुईस ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य आपूर्ति और अन्य बुनियादी जरूरतों को बनाए रखने के लिए प्रति माह 15 मिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी।

नेपाल के स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता अभियान में सहयोग करेगा भारत, सहयोग पत्र पर हुए हस्ताक्षर

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल के स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता अभियान में भारत ने पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए दोनों देशों ने एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर भी किये हैं। तीन दिनों के भारत दौरे पर गए नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव और भारत के जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच दिल्ली के दीनदयाल अंत्योदय भवन में बीच मुलाकात के दौरान यह करार हुआ है। दोनों नेताओं के बीच नेपाल के हर नागरिक के लिए स्वच्छ पेयजल के अभियान में पूर्ण सहयोग देने की बात हुई है।

भारत की यात्रा से लौटे नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच सहकार्य को एक नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संरक्षण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी सहयोग, अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत के जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के अनुभवों को साझा करते हुए समुदाय-आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे, जिससे जल एवं स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान नेपाल सरकार के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव देबश्री मुखर्जी, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अशोक कुमार मीणा सहित दोनों देशों के वरिष्ठअधिकारियों की उपस्थित थी।

इंडोनेशिया में बाढ़ के पानी के बीच से निकलते हुए लोग।

चीन की चालबाजी से परेशान ताइवान भी नागरिकता कानूनों को बना रहा सख्त

ताइपे। चीन की नीतियों के चलते ताइवान अपने नागरिकता कानूनों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है। ताइवान सरकार हांगकांग और मकाऊ के निवासियों के लिए नागरिकता पाने के वैकल्पिक रास्ते को खत्म करने और स्थायी निवास की पात्रता की शर्तों को सख्त करने पर विचार कर रही है।

एक रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि ताइवान सरकार हांगकांग और मकाऊ के निवासियों के लिए आव्रजन कानूनों में बदलाव कर सकती है। इसका मकसद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को ताइवान में घुसपैठ करने से रोकना है।

प्रस्तावित बदलावों के तहत चीन के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को ताइवान में स्थायी निवास पाने से पहले चार साल तक रहना होगा, जबकि अब यह समय एक साल है। इसके बाद वे स्थायी निवास प्राप्त करने के बाद ताइवान की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

रिपोर्ट में अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों के तहत, हांगकांग या मकाऊ के उन निवास आवेदकों की कड़ी जांच की जाएगी, जिन्होंने सीसीपी, चीनी सेना या चीनी सरकारी संस्थाओं के लिए काम किया है और उनके आवेदनों को संभवतः अस्वीकार किया जा सकता है।

यह कदम ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनी सुधार का हिस्सा है। ताइवान, हांगकांग में बदलती स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। 1997 के बाद से 2 मिलियन से ज्यादा चीनी लोग हांगकांग में बस चुके हैं। बता दें 1997 में ब्रिटन ने हांगकांग को चीन को सौंपा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद हांगकांग की स्थिति को काफी बदल दिया और चीनी प्रभाव को बढ़ाया। इन सब के चलते हांगकांग के लोगों के लिए ताइवान की आसान आव्रजन नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या बन गईं।

अधिकारी ने बताया कि चाहे वे ताइवानी से शादी करके आए हों, निवेश के जरिए आए हों या पेशेवर कौशल के आधार पर निवास प्राप्त किया हो, हांगकांग के प्रवासी अक्सर दूसरे साल में ही स्थायी निवास के लिए आवेदन करते हैं। हांगकांग और मकाऊ के कुछ प्रवासी ताइवान की नागरिकता में रुचि नहीं रखते, वे सिर्फ स्थायी निवास चाहते हैं।

यूरोपीय देश रूस से यूक्रेन की रक्षा करेंगे : कीर स्टार्मर

लंदन, (हि.स.)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कल यहां अहम घोषणा की। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध पर कहा कि हम इतिहास में चौराहे पर हैं। यूरोपीय देश रूस से यूक्रेन की रक्षा करेंगे। जरूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ गठबंधन तैयार किया जाएगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, स्टार्मर ने यह घोषणा लंदन में 18 यूरोपीय नेताओं की बैठक के बाद की। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी हिस्सा लिया। स्टार्मर ने कहा कि इस मसले पर कई अन्य देशों ने संकेत दिया है कि वह ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हैं। कीव और मॉस्को के बीच संघर्ष विराम की स्थिति में यूक्रेन में सेना तैनात कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन को 5,000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलें खरीदने के लिए ब्रिटिश निर्यात वित्तपोषण में 1.6 बिलियन पाउंड का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना की भी घोषणा की।

स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने शनिवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। उनका मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आने पर सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता सकता है। सीएनएन के अनुसार, लंदन के लैंकेस्टर हाउस में आयोजित शिखर सम्मेलन में कीर स्टार्मर ने कीव और वाशिंगटन के बीच मौजूदा तनाव महाद्वीप के लिए चिंता का विषय है। इसलिए यह अधिक बातचीत का क्षण नहीं है। यह कार्रवाई करने का समय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ जो हुआ, उससे मास्को का खुश होना स्वाभाविक है। स्टार्मर ने पत्रकारों से कहा कि वह लड़ाई रोकने की योजना तैयार करने के लिए फ्रांस और कुछ अन्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। योजना के अंतिम रूप लेते ही उसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। जेलेंस्की को लंदन यात्रा में खूब महत्व दिया गया है किंग चार्ल्स ने रविवार को अपने सैंड्रिंघम एस्टेट में जेलेंस्की से मुलाकात की।

नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सहयोग के लिए ट्रंप की प्रशंसा की

तेल अवीव, (हि.स.)। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में आतंकी समूह हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोग के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप दिखावा नहीं करते, वह दोस्ती को निभाते भी हैं। उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल गाजा में खाद्य आपूर्ति नहीं होने देगा।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर अपलोड किए वीडियो संदेश में यह बात कही। उन्होंने इस संदेश में वाशिंगटन की अपनी हालिया यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। इजराइल गाजा के संदर्भ में उनकी दूरदर्शी योजना का पूरी तरह समर्थन करता है। अमेरिका ने रुकी हुई सैन्य आपूर्ति भेजकर अपना अटूट समर्थन दोहराया है। यही नहीं, इजराइल को ईरान की आतंकी धुरी के खिलाफ काम करने के लिए हर संभव मदद दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में अस्थायी युद्धविराम को 50 दिनों तक बढ़ाने की योजना है। इस दौरान स्थायी युद्धविराम की शर्तों पर चर्चा की जा सकती है। इस योजना के तहत हमास को आधे बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। शेष को तब रिहा किया जाए जब हम स्थायी युद्धविराम पर किसी समझौते पर पहुंच जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल को यह योजना मंजूर है पर हमास ने इसे खारिज कर दिया है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने फिलहाल गाजा में खाद्य आपूर्ति रोकने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा जा रहा है कि हमास इसे जरूरतमंदों तक नहीं जाने देता। वह छीन लेता है। अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। नेतन्याहू ने दोहराया कि हमास इजराइल को अकेले न समझे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ढाल बनकर इजराइल के साथ खड़े हैं।

लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर, यूरोपीय आयोग के प्रेसीडेंट उर्सला वांडरलियोन, यूरोपीय काउंसिल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रीडू व अन्य यूरोपीय देशों के नेता एकसाथ नजर आये।

50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिकियों से क्यों लगा रहे गुहार

वर्साव। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यह एक विरोधाभास है कि 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वह 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर वाशिंगटन की स्थिति को दुविधा बताया और कहा कि हमें इस दुविधा से उबरने की जरूरत है।

बता दें व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात के बाद पौलैंड के पीएम टस्क ने यूक्रेन के समर्थन में बयान दिया। तब उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि प्रिय जेलेंस्की, प्रिय यूक्रेनी मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। ट्रंप, उनके डिप्टी जेडी वांस और जेलेंस्की के बीच ये बैठक कूटनीतिक मयार्दाओं से बाहर निकल गई थी। इस दौरान ट्रंप और जेडी की जेलेंस्की के साथ तीखी बहस हुई थी। ये बहस इतनी कटुतापूर्ण हो गई कि ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से बाहर जाने को कह दिया था। यही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में आयोजित डिनर को भी रद्द कर दिया।

बता दें कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से पोलैंड यूक्रेन का एक प्रमुख सहयोगी रहा है, जिसने टैंक, भारी उपकरण और गोला-बारूद समेत व्यापक सैन्य मदद दी है। पोलैंड में यूक्रेन के पूर्व राजदूत के मुताबक वारसॉ ने 2022 से कीव को 45 सैन्य मदद पैकेज दिए हैं, जिनकी कुल राशि 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। नाटो के सदस्य देशों में पोलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सबसे ज्यादा हिस्सा (4.7 फीसदी) रक्षा के लिए खर्च करता है।

व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत फेल होने के बाद पोलैंड के पीएम का बयान आया है। पौलेंड डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पोलैंड को अपनी राष्ट्रीय और यूरोपीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के रूप में अतिरिक्त इंश्योरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। टस्क ने कहा कि यूरोप को महाद्वीप की सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यह एक विरोधाभास है, यह कैसा लगता है, 500 मिलियन यूरोपीय 300 मिलियन अमेरिकियों से 140 मिलियन रूसियों से उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। यदि आप गिनना जानते हैं, तो खुद पर भरोसा करें।

पोलिश पीएम ने जोर देकर कहा कि यूरोप वर्तमान में कल्पना और साहस की कमी से ग्रस्त है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों की सेना में 2.6 मिलियन सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के पास 1.3 मिलियन, चीन के पास 2 मिलियन और रूस के पास 1.1 मिलियन सैनिक हैं। टस्क ने कहा कि यूरोप को सभी पर बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा कि यही बात लड़ाकू विमानों पर भी लागू होती है। यूक्रेन के साथ यूरोप के पास 2,091, अमेरिका के पास 1,456, चीन के पास 1,409 और रूस के पास 1,224 लड़ाकू विमान हैं।

गौरतलब है कि वाशिंगटन में जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत फेल होने के बाद यूक्रेन जंग पर विचार करने के लिए नाटो देश लंदन में जुटे हैं। यहां पौलेंड के डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यूरोप जाग गया है।

यूरोपीय संघ, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, तुर्की सभी एक स्वर में यूक्रेन की मदद, ट्रांसअटलांटिक सहयोग की जरुरत और पूर्वी सीमा को मजबूत करने के बारे में कह रहे हैं।

Page-07_Layout 1 3/3/2025 10:45 PM Page 1

मैक्सको में मैरिडा ओपन टेनिस में ट्रॉफी के साथ नजर आयीं अमेरिका की इमा नवारो।

आईपीएल 2025 : केकेआर ने लॉन्च की थ्री-स्टार जर्सी, तीन खिताबी जीत को समर्पित

कोलकाता, (हि.स.)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 18वें सीजन के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण किया। इस बार टीम ने एक अनूठे अभियान के तहत नंबर 3 की थीम पर जोर दिया, जिसमें प्रशंसकों को केकेआर की तीन खिताबी जीत की याद दिलाई गई है।

इस अभियान का आकर्षण थ्री स्टार डिजाइन रहा, जिसे जर्सी के फैब्रिक में शामिल किया गया है।

ये तीन सितारे केकेआर के 2012, 2014 और 2024 में जीते गए तीन आईपीएल खिताबों का प्रतीक हैं। आधिकारिक जर्सी लॉन्च वीडियो में रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रामदीप सिंह, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय, मयंक मार्कंडे और लवनीत सिसोदिया जैसे खिलाड़ी नई जर्सी में नजर आए।

इस साल केकेआर की नई जर्सी पर टीम के लोगो के ऊपर तीसरा सितारा जोड़ा गया है। इसके अलावा, एक स्पेशल गोल्डन टाटा आईपीएल बैज भी जर्सी की बाजू पर लगाया गया है, जिसे टूर्नामेंट ने 2025 के डिफेंडिंग चैंपियन के सम्मान में पेश किया है।

नई जर्सी को थ्री-एन्ड स्टार डिजाइन के साथ तैयार किया गया है और इसे एक साथ बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया गया है। प्रशंसक इसे नाइट क्लब (केकेआर का आधिकारिक ऐप), वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीद सकते हैं।

गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक होंगे मुकाबले, ताजा बर्फबारी के बाद मिली हरी झंडी

नई दिल्ली, (हि.स.)। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 (केआईडब्ल्यूजी 2025) का दूसरा चरण अब जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक आयोजित होगा। पहले यह खेल 22 से 25 फरवरी के बीच होने थे, लेकिन कंगडूरी स्लोप्स और गोल्फ कोर्स पर पर्याप्त बर्फ न होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था।

पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में आयोजित किया गया था, जहां आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतिस्पधाएं हुई थीं।

अब गुलमर्ग में होने वाले दूसरे चरण में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग के मुकाबले खेले जाएंगे।

आयोजन समिति के बयान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी और मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए अब खेलों के तकनीकी संचालन के लिए स्थिति अनुकूल पाई गई है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेलों के स्थगन के बाद इसकी मेजबानी को लेकर संदेह बना हुआ था।

गुलमर्ग में होने वाले खेलों में भारत के शीर्ष स्कीयरों के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि फरवरी में हुए एशियन विंटर गेम्स 2025 (हरबिन, चीन) के बाद अधिकतर खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। इस बार खेल मंत्रालय भी शीतकालीन खेलों को विशेष बढ़ावा दे रहा है। पहली बार भारतीय दल को एशियन विंटर गेम्स में भाग लेने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता भी दी गई थी।

इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से घरेलू खेल कैलेंडर की शुरूआत हुई। प्रधानमंत्री ने भी इन खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह भारत को एक प्रमुख खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। लद्दाख में हुए पहले चरण में 19 टीमों ने भाग लिया, जिनमें राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और संस्थान शामिल थे। लद्दाख ने चार स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में बढ़त बनाई।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरूआत 2020 में हुई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर पहले तीन संस्करणों की मेजबान और विजेता रही। 2024 संस्करण लद्दाख और जम्मू-कश्मीर ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था, जिसमें भारतीय सेना ने ओवरऑल खिताब जीता था।

कृष्णा जयशंकर ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारत की कृष्णा जयशंकर ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 22 वर्षीय कृष्णा ने 16.03 मीटर के प्रयास के साथ न केवल पोडियम पर जगह बनाई, बल्कि भारतीय इनडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नेवादा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा ने शनिवार को हुए फाइनल में अपने अंतिम प्रयास में 16.03 मीटर का थ्रो फेंका, जिससे उन्होंने 2023 में महाराष्ट्र के पूणार्राव राणे द्वारा स्थापित 15.54 मीटर के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस प्रतियोगिता में कोलोराडो विश्वविद्यालय की मैया लेंसर ने 19.02 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी गैबी मोर्न्स ने 17.09 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।

हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप: असम ने बिहार को 2-1 से हराया

पंचकूला, (हि.स.)। ताऊ देवी लाल हॉकी स्टेडियम, पंचकूला में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के डिवीजन बी के तीसरे दिन सोमवार को असम हॉकी ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को 2-1 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की।

मैच की शुरूआत से दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहला क्वार्टर बिना किसी गोल के समाप्त हुआ, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले असम हॉकी की कप्तान मुनमुनी दास (29') ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद असम हॉकी ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाते हुए तीसरे क्वार्टर तक अपनी बढ़त बनाए रखी।

मैच के अंतिम क्षणों में रोमांच और बढ़ गया। खुशबू प्रजापति (59') ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर असम हॉकी की बढ़त को 2-0 कर दिया। हालांकि, अगले ही मिनट में नुसरत खातून ने बिहार की ओर से एकमात्र गोल कर अंतर कम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इस जीत के साथ असम हॉकी ने अंकतालिका में अपना खाता खोल लिया, जबकि हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को अब भी पहली जीत की तलाश है।

इससे पहले रविवार को डिवीजन सी के मैच में हॉकी आंध्र प्रदेश ने पूल बी के खेल में हॉकी जम्मू और कश्मीर के खिलाफ 4-2 से जीत दर्ज की। रेवती थालारी (3, 17) ने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण दो गोल किए, जबकि हरथी लोमाडा (36) और मदुगुला भवानी (45) ने भी हॉकी आंध्र प्रदेश के लिए गोल किए।

रजनी (10) और अंजू कुमारी (57) हॉकी जम्मू और कश्मीर के लिए गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं।

रविवार के आखिरी डिवीजन सी मैच में, ले पुडुचेरी हॉकी ने पूल बी में हॉकी अरुणाचल पर 6-1 से शानदार जीत हासिल की। जयप्रथा एस (13, 39, 41) ने शानदार हैट्रिक बनाई, जबकि अन्य तीन गोल बी दीपिका (4, 22) और एस सुबासरी (40) ने किए। हॉकी अरुणाचल के लिए हेमा नवैत (5) एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी रहीं।

चीन में बहरीन की टिजिस्टा गैसो महिलाओं की मैराथन में फिनिश लाइन पार करने के बाद उत्साहित होती हुई।

दिल्ली

सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को लोक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। यह रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 को सदन में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कई गंभीर चूक और अनियमितताओं को उजागर किया गया है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी।

सीएजी द्वारा किए गए इस लेखा परीक्षण में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को कवर किया गया, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। सीएजी रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्टों की भारी कमी दर्ज की गई। मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण कई अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थे। अत्यधिक खराब एंबुलेंस सेवाएं, अधिकांश कैट्स एंबुलेस आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के बिना संचालित हो रही थीं। स्वास्थ्य विभाग उन 15 भूखंडों का उपयोग करने में असफल रहा, जिन्हें विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधिग्रहित किया गया था। हर वर्ष बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए आवंटित बजट का 78.41 फीसद हिस्सा अनुपयोगी रह गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि सदन की लोक लेखा समिति इस सीएजी रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी और तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सचिवालय इस रिपोर्ट को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा और स्वास्थ्य विभाग को एक माह के भीतर अपनी अनुपालन कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, इसलिए सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

लूटपाट के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली, (हि.स.)। उत्तर-पूर्वी जिले के सोनिया विहार इलाके में एक युवक को हथियार दिखाकर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान विकास मिश्रा उर्फ नमन (26) और अर्जुन कुमार (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि रविवार शाम के समय वेद विहार लोनी निवासी एक युवक कुलदीप शर्मा (32) सोनिया विहार थाने में शिकायत लेकर पहुंचा था। कुलदीप ने बताया कि शनिवार शाम को वह दिल्ली पुलिस अकादमी से होता हुआ लोनी की ओर जा रहा था।

विधानसभा की कार्यवाही की फोटो एक्स पर अपलोड कर फंस गए आप विधायक जरनैल सिंह

नई दिल्ली, हि.स.)। दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सोमवार को आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह के एक्स पर सदन की फोटो पोस्ट करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। जरनैल सिंह ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिना मंत्रियों के सदन में चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से जवाब कौन देगा? आआपा विधायक की इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा विधायक दीपक चौधरी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर (नियमों के उल्लंघन के संबंध में प्रस्ताव) ले आए। इसके बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को लेकर जरनैल सिंह से कहा कि वो पोस्ट डिलीट करके माफी मांगें। अध्यक्ष ने कहा कि ये विशेषाधिकार हनन का मामला है। पोस्ट को डिलीट करें। आपने सदन में फोटो क्यों खींची। सदन से माफी मांगें और कहें कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस पर जरनैल सिंह ने कहा कि सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या वो अपराध है? फिर मैं लाइव टेलीकास्ट डाल देता हूं। इस पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की फोटो खींचना गरिमा के अनुकूल नहीं है।

उसके बाद जरनैल सिंह ने कहा कि फोटो डालने का विषय अनुचित है तो खेद प्रकट करता हूं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाइव टेलीकास्ट अध्यक्ष की अनुमति से होता है। आपने जो किया, वह नियम का उल्लंघन है। आपने खेद प्रकट किया, कोई भी पक्ष या विपक्ष इस तरह सदन का विशेषाधिकार हनन न करे। उन्होंने कहा कि ये नियम 261/25 का उल्लघंन है। सदन के सदस्य ने खेद प्रकट किया है। भविष्य में ऐसा ना करें। सदन आप से कह रहा है कि आप तुरंत फोटो डिलीट करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के मुद्दे पर चर्चा करें।

भाजपा विधायक अजय महावार ने सदन में कहा कि आआपा विधायक जरनैल सिंह का फोन जब्त किया जाए। ताकि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो। सुबह से दस बार प्रेम जी पोस्टर लहरा चुके हैं। बार-बार मना करने पर भी मानते नहीं हैं। अभी पहला बजट भी नहीं आया। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि ये सदन नियमों से चलता है। नेता विपक्ष आतिशी हर बात पर खड़ी हो रही हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हमने वीडियो बनाए, सबूत दिखाएं। आतिशी बचकानी हरकतें कर रही हैं।

दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह संवाददाताओं से बातचीत करते हुए।

केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का काला चिट्ठा सीएजी रिपोर्ट ने खोला : पंकज सिंह

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को विधानसभा सत्र में सीएजी की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का काला-चिट्ठा सीएजी की रिपोर्ट ने खोला है। उन्होंने बताया कि सीएजी रिपोर्ट में अस्पतालों में 21 फीसद स्टाफ की कमी और एंबुलेंस आवश्यक उपकरणों के बिना चलाने की बात है। इसके अलावा अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, शवगृह, ऑक्सीजन, एंबुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं हुई। हीमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए इंजेक्शन भी अस्पतालों में नहीं उपलब्ध थे।

पंकज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी वाले जिला अनुसार क्षेत्रों का कभी आंकलन नहीं किया गया। न ही अस्पतालों में बेड और नये भवन की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए अध्ययन किया गया।

भगवान महावीर अस्पताल में स्थापित 25 डायलिसिस मशीनें उपयोग में नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी हुई खराब हो गईं। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना से त्रस्त था, तब कट्टर बेईमान आआपा सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा देकर मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जांच के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार उपकरण और दवाइयों की खरीद करने में पूरी तरह विफल रही है। केजरीवाल सरकार द्वारा काली सूची में शामिल कंपनियों से दवाइयों की खरीद करने की बात सामने आई है।

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट का पूर्ण उपयोग भी केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 100 दिन में दिल्ली के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव दिखेगा, जन औषधि योजना पर भी काम होगा और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा।

भाजपा विधायक शिखा राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को मजाक बनाकर रख दिया था। सीएजी रिपोर्ट से साफ है कि 43 प्राइवेट अस्पतालों के लिए सिर्फ 22 लाइजन ऑफिसर नियुक्त किए गए, 12 को एक से अधिक की देखरेख करने के लिए छोड़ दिया गया और 14 में कोई भी लाइजन ऑफिसर नियुक्त ही नहीं किया गया। दस लाख से ज्यादा शिकायतों का कोई निवारण नहीं किया गया। 2016 से 2022 तक लोकनायक अस्पताल द्वारा हर दिन एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में रेफेर किया जाता था जबकि लोक नायक अस्पताल में तीन हजार मरीज ओपीडी में देखे जाते थे।

Page-08_Layout 1 3/4/2025 3:07 AM Page 1

मुख्यमंत्री का निर्देश, अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर।

योगी सरकार ने शहरी बाढ़ नियंत्रण की दिशा में उठाया बड़ा कदम

दिव्य भारत संवाददाता

- **लखनऊ, मेरठ, शाहजहांपुर सहित अन्य नगर निगमों में आधुनिक जल निकासी प्रणाली पर किया जा रहा काम**
- **करीब 750 करोड़ की लागत से इन शहरों में विकसित किया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम, नालों का पुनर्विकास और निर्माण**

लखनऊ। योगी सरकार शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अभी से एक्टिव मोड में आ गयी है। इसके लिए नगर विकास विभाग को जलभराव, बाढ़ से बचाव के लिए आधुनिक तकनीकों, जल निकासी प्रणाली के सुधार और नदी तटों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। इसी के तहत लखनऊ, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर सहित अन्य नगर निगमों में आधुनिक जल निकासी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने करीब 750 करोड़ की धनराशि जारी की है। इससे इन शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, नालों का पुनर्विकास और निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शहरों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और बाढ़ नियंत्रण उपायों को लेकर बैठक की थी। इस दौरान सीएम ने नगर विकास विभाग और जल निगम को शहरों में सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिये। साथ ही नालों की नियमित सफाई, जलभराव रोकने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली को बढ़ावा देने और बाढ़ नियंत्रण के लिए नए पंपिंग स्टेशन बनाने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल निकासी को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, इससे जलभराव को कम किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों में बाढ़ से बचाव हेतु विशेष योजनाएं चल रही हैं। इन शहरों में जलनिकासी चैनलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ताकि रीयल-टाइम मॉनिटरिंग हो सके और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

सीएम ने बैठक में लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा और शाहजहांपुर में ड्रेनेज सिस्टम को डवलप करने के लिए 733 करोड़ की धनराशि जारी की है। इससे लखनऊ में किला मोहम्मदी नाला का पुनर्विकास होगा। इसके लिए 193.73 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 10.571 किलोमीटर लंबी जल निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे 2.5 लाख की आबादी को राहत मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

जवाबदेही व कार्यों के मूल्यांकन से होगा संगठन मजबूत : प्रमोद तिवारी

अजीत प्रताप सिंह/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता मा. सांसद प्रमोद तिवारी जी के ढकवा पहुंचाने पर पट्टी ब्लॉक अध्यक्ष विवेक पांडेय, पट्टी विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी सुनीता पटेल व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा के संयुक्त नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया।' स्वागत के उपरांत कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मा. प्रमोद तिवारी ने कहा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में संगठन सृजन अभियान का कार्य जोरों पर है आप सभी भी संगठन सृजन अभियान के तहत गांव गांव घर-घर जाकर सभी वर्गों और सभी जातियां के लोगों से मुलाकात कर एक बूथ 10 यूथ के तहत संगठन को मजबूत करिए, सभी कार्यकर्ता 2027 चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करें।'

यूपी एनसीसी के कैडेटों ने मेला क्षेत्र में जारी स्वच्छता अभियान में किया योगदान

दिव्य भारत संवादाता

प्रयागराज। प्रयागराज में संगम तट पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आस्था के महापर्व महाकुम्भ का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 फरवरी को महाकुम्भ के समापन की घोषणा के अवसर पर मेला क्षेत्र में 15 दिनों विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी दिशा क्रम में संगम तट पर चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान में सोमवार को यूपी एनसीसी के कैडेटों ने वालेंटियर के तौर पर भाग लिया। आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस तथा अन्य सामाजिक संस्थाएं भी महाकुम्भ के स्वच्छता अभियान में सहयोग देंगी। आस्था के महापर्व महाकुम्भ के समापन के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का क्रम निरंतर जारी है। पवित्र संगम में स्नान के लिए संगम तट को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान मेले की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राना के निर्देशन में चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी एनसीसी के 30 कैडटों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। यूपी एनसीसी के नायब सूबेदार गुरुबचन सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र के सेक्टर 21 में चल रहे स्वच्छता कार्यक्रम में उनकी बटालियन ने अपना योगदान दिया।

प्रोजेक्ट प्रवीण योजना को वृहद स्वरूप में शुभारम्भ करायें : डा. दिव्या मिश्रा

दिव्य भारत संवादाता

प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा द्वारा विकाश भवन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ बैठक कर 4 मार्च को प्रोजेक्ट प्रवीण योजना के वृहद स्वरूप शुभारम्भ करने के लिए जिला समन्वयक उ0प्र0 कौशल विकास मिशन की देखरेख में कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला समन्वयक एमआईएस आलोक कुमार ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के प्रोजेक्ट प्रवीण योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अध्यनरत कक्षा-9 एवं 11 के छात्र/छात्रायें कौशल वर्द्धन हेतु निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। शासन द्वारा प्रथम चरण में जनपद के 3 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। जीआईसी सदर एवं जीजीआईसी खरवई में हेल्थकेयर सेक्टर का फाउन्डेशन कोर्स एवं राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज मानिकपुर में बीएफएसआई सेक्टर के अन्तर्गत बैंक आफिस एसोशिएट/फाइनेंशियल सर्विसेस का कोर्स कराया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद सफल प्रशिक्षणार्थियों को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जायेगा।

महाकुम्भ में 15 देशों, 20 राज्यों के बिछड़ों को यूपी के जवानों ने अपनों से मिलवाया

आशीष पाण्डेय

प्रयागराज। महाकुम्भ में उमड़े आस्था के महासमुद्र के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन के जवानों ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की अद्वितीय मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचालित विशेष अभियान के तहत जवानों ने 15 देशों और 20 से अधिक राज्यों के बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलाया। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने न केवल लाखों रुपये की नकदी, आईफोन, गहने और अन्य कीमती सामान खोने वालों को लौटाए, बल्कि बीमारों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खाकी ने बड़ी संख्या में बुजुर्गों को संगम में स्नान करने में उनकी मदद भी की। बीमारों को सीपीआर से लेकर प्राथमिक उपचार तक दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप योगी सरकार की कार्यकुशलता की गूंज रूस-अमेरिका और जर्मनी समेत तमाम देशों तक पहुंच गई।

गेहूं क्रय केन्द्र के आस-पास आढ़तिये भटकने न पाये : जिलाधिकारी

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। कैम्प कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद कार्यशाला सम्पन्न हुई। बैठक में खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 67 गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये है,जिनमें खाद्य विभाग के 26, पी0सी0एफ0 के 28, पी0सी0यू0 के 9 और भारतीय खाद्य निगम के 4 सम्मिलित है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 2425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। जिले में 3284 कृषकों द्वारा गेहूं विक्रय के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर आधार कार्ड, खसरा/खतौनी, पहचान पत्र, पंजीकरण कागज लेकर आना अनिवार्य होगा। पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के आधार लिंक खाते में भुगतान किया जायेगा। जिलाधिकारी जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने सभी गेहूं क्रय केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया कि 15 मार्च से पहले गेहूं क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र, छलना आदि सारे उपकरण की उपलब्धता क्रय केन्द्रों पर सुनिश्चित करायें। क्रय केन्द्र पर क्रय पंजिका, स्टॉक बुक, टोकन पंजिका, गेहूं प्रेषण रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका एवं कृषक से खरीद सम्बन्धी अभिलेख अवश्य उपलब्ध रहे। शासन की गाइडलाइन प्राप्त होने पर क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद प्रारम्भ कर दी जाये।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि गेहूं क्रय केन्द्र के आस-पास आढ़तियें कदापि न भटकने पाये, यदि ऐसा पाया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी इसकी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को देगें। अगर नही देते है तो सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। यदि केन्द्र के आस आढ़तिया न आने पाये केन्द्र प्रभारी जिम्मेदारी तय की जायेगी, उसकी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को देगें। यदि सूचना नही देता है तो क्रय केन्द्र बन्द कर दिया जायेगा। उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर आवश्यक अभिलेखों को देख लें एवं जो भी कमियां पायी जाये उसे दुरूस्त करा दें। गेहूं क्रय केन्द्रों पर बैनर पोस्टर लगाये जाये उसमें केन्द्र का नाम, मोबाइल नम्बर, केन्द्र प्रभारी का नाम, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अंकित किये जाये। समस्त तहसीलों में एक-एक होर्डिंग लगायी जाये। सभी गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरो की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था, किसानों हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाये।

सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद के समय इलेक्ट्रानिक कांटा शत प्रतिशत संचालित रहे। बाट माप अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त क्रय केन्द्रों के इलेक्ट्रानिक कांटों का सत्यापन कर लिया जाये जिससे खरीद के समय किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाये।

यूपी में हथकरघा और वस्त्रोद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयारी में योगी सरकार

दिव्य भारत संवाददाता

- **यूपी के कपड़ा उद्योग को मिलेगी नई पहचान, बुनकरों और उद्यमियों को होगा लाभ**
- **प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी योगी सरकार**
- **पावरलूम बुनकरों को मिलेगी सस्ती बिजली, प्रदेश बनेगा टेक्सटाइल हब**

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व व निर्देशन में यूपी का हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में यह उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं 80 हजार से अधिक परिवार इस कार्य में संलग्न हैं। वहीं, 2.58 लाख पावरलूम के माध्यम से 5.50 लाख से अधिक बुनकरों को रोजगार मिल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जिससे बुनकरों और उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनने वाले ये पार्क वस्त्र उद्योग को आधुनिक तकनीकों से लैस करेंगे और उत्पादन लागत को कम करके उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

महाकुम्भ में इस्तेमाल ऑटोमैटिक मशीनों से पूरे यूपी को बनाएंगे इंसेक्ट फ्री

दिव्य भारत संवादाता

- **मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रयागराज में किया गया मिस्ट ब्लोअर और मिनी फॉगिंग मशीनों का सफल संचालन**
- **नगर निगमों को मिलेंगी मच्छर-मक्खी से बचाने वाली अत्याधुनिक 107 ब्लोअर मिस्ट मशीनें**
- **स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएंगी 110 मिनी फॉगिंग मशीनें**
- **अखाड़ों को इंसेक्ट फ्री बनाने में रही कारगर, अब विभिन्न जिलों में होंगी इस्तेमाल**
- **डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के नियंत्रण में यह मिनी फागिंग मशीन बेहद कारगर**
- **कॉल करते ही 30 मिनट में लोगों तक पहुंचेगी ऑटोमैटिक मशीन**
- **मच्छर-मक्खी मुक्त महाकुम्भ के बाद पूरे यूपी में तैनात होंगी मूविंग वेक्टर कंट्रोल यूनिट**
- **संतों और श्रद्धालुओं के बाद अब यूपी की जनता की हिफाजत और सुविधाओं की होगी रैंडम चेकिंग**

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुम्भ में इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक मिस्ट ब्लोअर और मिनी फॉगिंग मशीनों का प्रयोग अब पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। महाकुम्भ में इन मशीनों का सफल इस्तेमाल किया गया था। जिससे संतों और श्रद्धालुओं को मच्छरों और मक्खियों से राहत मिली। अब इन्हीं मशीनों को विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। जिससे प्रदेश को इंसेक्ट-फ्री बनाया जा सके। इस तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जाएगा। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीनें नगर निगमों और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएंगी। महाकुम्भ में संतों और श्रद्धालुओं को मच्छर-मक्खी से बचाने वाली अत्याधुनिक 107 ब्लोअर मिस्ट मशीनें नगर निगमों को सौंपे जाने की तैयारी है। वहीं, 110 मिनी फॉगिंग मशीनें स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएंगी। अखाड़ों को इंसेक्ट फ्री बनाने में कारगर ये मशीनें अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस्तेमाल की जाएंगी। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के नियंत्रण में यह मिनी फागिंग मशीन बेहद कारगर है। सबसे खास बात यह है कि कॉल करते ही ये ऑटोमैटिक मशीन 30 मिनट के भीतर लोगों तक पहुंचने में सक्षम है। महाकुम्भ के नोडल जॉइंट डायरेक्टर (वेक्टर कंट्रोल) डॉ वीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश के नगर निगमों को 107 ब्लोअर मिस्ट मशीनें सौंपी जाएंगी। यह कूड़े और गंदगी पर छिड़काव में काफी मददगार साबित होंगी। वहीं, स्वास्थ्य विभाग को 110 मिनी फॉगिंग मशीनें सौंपी जाएंगी। जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर प्रभावी रोक लगाने के सक्षम रहेंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी इनका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सफाई और वेक्टर नियंत्रण में भी इनसे बड़ी मदद मिलेगी।

मेले में वेक्टर कंट्रोल के असिस्टेंट नोडल और डीएमओ डॉ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि महाकुम्भ में इस्तेमाल की गई ऑटोमैटिक ब्लोअर मिस्ट मशीनें इतनी प्रभावी रहीं कि कॉल करने के 30 मिनट के भीतर किसी भी स्थान पर पहुंच सकती हैं। इसी तर्ज पर अब मूविंग वेक्टर कंट्रोल यूनिट पूरे प्रदेश में संचालित की जाएगी। ताकि किसी भी इलाके में संक्रमण या मच्छरों की समस्या होने पर तुरंत फॉगिंग और मिस्ट ब्लोअर से छिड़काव किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर मच्छर-मक्खियों से बचाव के लिए व्यापक सेवा शुरू की जा रही है। अब आम जनता को भी तत्काल सुविधाएं मिल सकेंगी। इन मशीनों के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

महाकुम्भ में पेट्रोल से चलने वाली ब्लोअर मिस्ट मशीनों से बड़े पैमाने पर छिड़काव कार्य किया गया। अब यह मशीनें नगर निगमों को सौंपी जाएंगी। जिससे कूड़े और गंदगी पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित होगी। क्योंकि बाढ़ के बाद गंदगी और मच्छरों के बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। जब डेंगू या मलेरिया का कोई मामला सामने आएगा, तो मरीज के घर और उसके आसपास 50 घरों में वेक्टर नियंत्रण के तहत छिड़काव किया जाएगा। इस अभियान में यह मिनी फॉगिंग मशीनें बेहद प्रभावी साबित होंगी और डेंगू-चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

महाकुम्भ में सफलता के बाद अब यूपी सरकार इस तकनीक को पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। इससे मच्छर-मक्खियों से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकेगा। साथ ही प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

बदलता जायका प्राकृतिक उत्पादों के लिए बेहतर मौका

आलोक पाण्डेय/दिव्य भारत

- **लोग स्थानीय उत्पादों और उसमें मिलने वाले पोषक तत्वों को दे रहे वरीयता**
- **ओडीओपी में शामिल कृषि उत्पादों के लिए यह बेहतरीन मौका**

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड 19 के बाद देश दुनिया में लोगों की फूड हैबिट्स में बदलाव आया है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (बीएमइएल) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चार में से तीन लोग अब क्षेत्रीय स्वाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग ऐसे उत्पादों का उच्च गुणवत्ता वाला मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से अब क्षेत्र की कई नामचीन कंपनियां विविधता के साथ स्थानीयता पर फोकस कर रही हैं।

यह स्थित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के नारे को साकार करने का एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश और यहां के उन किसानों लिए तो और भी जो इस तरह प्राकृतिक/जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि योगी सरकार ने सात साल पहले जिस एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) की घोषणा की थी उनमें कई उत्पाद खेतीबाड़ी से ही जुड़े हैं। मसलन सिद्दार्थनगर का काला नमक धान, मुजफ्फर नगर एवं अयोध्या का गुड़, कुशीनगर का केला, प्रतापगढ़ का आंवला आदि।

ओडीओपी योगी सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। साथ ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर सरकार का पूरा फोकस है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार ऐसी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों को देश दुनियां के भोजन के ट्रेंड में आए इस बदलाव का लाभ होना स्वाभाविक है।

फूड और फूड हैबिट्स के क्षेत्र में काम करने वाली एक नामचीन कंपनी इनोवा मार्केटिंग रिसर्च के अनुसार कोविड के बाद स्वास्थ्य के पहलू का अब भोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वाद के साथ जो खा रहे हैं उसमें मिलने वाले कैलोरी, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन आदि को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्वाभाविक है कि जिन चीजों में इनकी उपलब्धता है उनकी मांग भी बढ़ी है। ताजी सब्जियां, मौसमी फल आदि इनमें शामिल हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति आई इस जागरकता के कारण कई कम्पनियों को अपने उत्पाद में चीनी, फैट और सोडियम की मात्रा कम करनी पड़ी है।

नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायकोनॉलिग्स्ट) डॉक्टर तृप्ति दुबे यादव का कहना है कि जैसे जैसे शिक्षा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी लोग सेहत के प्रति भी और जागरूक होते जाएंगे। ऐसे में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जैविक उत्पादों के लिए तो और भी। चूंकि उत्तर प्रदेश उस इंडो गंगेटिक बेल्ट में आता है जहां की जमीन का शुमार दुनिया की सबसे उर्वर भूमि में होता है। नौ तरह के एग्रो क्लाइमेट जोन (कृषि जलवायु क्षेत्र) के कारण वहां हर तरह के खाद्यान्न, सब्जियों एवं फलों के की खेती हो सकती है। सरकार का खेतीबाड़ी से लेकर प्राकृतिक खेती पर फोकस भी है। ऐसे में वहां के किसानों को तो लाभ होगा। ऐसे उत्पादों के प्रयोग से लोगों की सेहत संबंधी होने वाला लाभ बोनस होगा।

संगम क्षेत्र में कम हुआ मां गंगा का जल, दिखने लगी बालू।